कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

ISSN-0447-2500

वर्ष 60 अंक 11 मुंबई नवम्बर 2016

लुधियाना में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 60 अंक 11 मुंबई नवम्बर 2016

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष
उषा सुरेश

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुलवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित

टेलिफैक्स: 022-26719465

ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 31

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार समारोह

खादी में ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक सुधार...मोदी........

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति..हब...............

प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ.............................

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के भाषण का मूल पाठ..

प्रधानमंत्री द्वारा एससी/एसटी हब और जेड स्कीम.........

प्रधानमंत्री द्वारा 500 पारंपरिक काष्ठ चरखों का वितरण..

आयोग ने नई खादी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए.........

आयोग का नए क्षेत्र में प्रवेश : बाल निरिक्षण गृह में........

दिल्ली के आधारशिला बाल निरिक्षण गृह में खादी.........

अहमदाबाद में खादी उत्सव-2016 का आयोजन..........

आयोग ने बिक्री में दर्ज किये नये रिकॉर्ड......................

आयोग द्वारा किशोर अपराधियों को प्रशिक्षण देने के.......

मुंबई में खादी उत्सव-2016 का आयोजन...................

आयोग द्वारा ग्रीन चैनल के माध्यम से रेलवे को खादी......

आयोग के अध्यक्ष द्वारा लोक जागृति सेवा संघ ट्रस्ट.........

आयोग की 638वीं बैठक का कार्यवृत्त.........................

केरल में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम कार्यान्वयन.........

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..........27 से 35

आजादी के पहले 'खादी फॉर नेशन', आजादी के बाद 'खादी फॉर फैशन'

खादी में ग्रामीणों के जीवन में आर्थिक सुधार लाने की क्षमता हैः मोदी

लुधियाना, 18 अक्टूबर 2016ः एक समय था जब खादी को स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अस्त्र के रूप में उपयोग किया गया था, अब खादी को फैशन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यह बात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह में एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और कॉयर क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले एमएसएमई उद्यमियों, खादी संस्थाओं, कत्तिनों, बुनकरों, खादी इण्डिया भवनों, खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों, खादी पूनी संयंत्र तथा बैंकों के पुरस्कार विजेताओं एवं प्रतिनिधियों के एक भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए 500 लकड़ी के चरखे वितरित किये। चरखा वितरण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी हमारे लिए एक प्राथमिकता है और एक चरखा .....घर में और अधिक आय लाता है।

उन्होंने खादी के विपणन पर जोर देते हुए कहा कि इन दिनों जो खादी पर हम बल दे रहे हैं, सूत के काम पर दाम बढ़ा रहे हैं, इन सबका नतीजा ये है कि जिस परिवार में एक चरखा है, करीब-करीब उन माताएं-बहनें की औसत 150 रुपए से ज्यादा प्रति दिन उनकी कमाई हो रही है। एक प्रकार से गृह उद्योग एवं खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी का जो सपना था, अर्थव्यवस्था की इस नींव को भी मजबूत करने की दिशा में आज यह महत्वपूर्ण काम खादी के द्वारा किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि पहले जो हम सोचते थे, वो जमाना बदल चुका है आज खादी की क्वालिटी देखें, खादी का पैकेजिंग देखें, खादी कॉर्पोरेट जगत में प्रतिस्पर्धा करे, उस रूप में खादी ने आप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और एक बात सही है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो खादी का अपना एक महत्व था। उस समय का मंत्र था, 'खादी फॉर नेशन', अब देश आजाद है। हमें आर्थिक क्रान्ति की ओर जाना है और इसलिए आज का मंत्र है, 'खादी फॉर फैशन'। आजादी के पहले जो 'खादी फॉर नेशन', आजादी के बाद 'खादी फॉर फैशन'। अगर खादी को

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

हम बढ़ावा देते हैं तो वह भी गांव, गरीब, सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में, बदलाव लाने की एक ताकत रखता है और मैं लोगों से हमेशा आग्रह करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने। नीचे से ऊपर तक हर चीज खादी की हो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। लेकिन आपके घर में पचासों प्रकार के वस्त्र होते हैं तो कुछ खादी के भी तो वस्त्र के परिधान होने चाहिए। अगर हिन्दुस्तान के हर परिवार में कुछ न कुछ खादी का होगा और दिवाली के समय अगर हम कुछ न कुछ खादी खरीदते हैं तो गरीब के घर में दीवाली का दीया जलता है।

उन्होंने उद्यमियों से जेड योजना (जीरो डिफेक्टस, जीरो इफेक्ट्स) में भाग लेने का भी आग्रह किया कि इसके तहत "कम से कम 10 लाख इकाइयों को आगे आना चाहिए। हमने जेड प्रमाणन मानक को पूरा करने के लिए 50 मानकों को स्थापित किया है। प्रधान मंत्री ने कहा, इन मानकों का पालन करने के लिए उद्यमी अपने आप को सक्षम बनायें"।

प्रधानमंत्री ने मुख्य समारोह में एमएसएमई की दो नई योजनाओं का शुभारंभ किया। यह योजनाएं हैं- एमएसएमई हेतु जेड प्रमाणन योजना (जीरो डिफेक्टस, जीरो इफेक्ट्स) तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एससी-एसटी हब योजना। उन्होंने कहा, इससे हमें उन दलितों उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता की भावना पैदा करने में फायदा होगा, जो युवा उद्यमों और रोजगार के अवसर पैदा करने का सपना संजोए हुए हैं, "समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। "हमारा उद्देश्य वैश्विक बाजार को लक्षित करने के लिए होना चाहिए"। 490 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ, बाजार पहुंच /लिंकेजज, निगरानी, क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए तथा वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की दिशा में काम करने के लिए, हब योजना का शुभारंभ किया गया।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। विशेष रूप से उद्यमियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उनसे कंधे से कंधा मिलकर उनके सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

प्रधान मंत्री ने कहा, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आज विश्व की तेज गति से आगे बढ़नी वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें हिन्दुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, दो वर्ष आकाल होने के बावजूद भी। हमारा किसान परेशान था, कृषि उत्पादन में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी, उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने खासकर इन सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने एक कमाल करके दिखाया और भारत की विकास दर को न सिर्फ नीचे आने दिया, इतना ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान किया।

प्रधानमंत्री दलितों की हालत पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर दलितों और दबे-कुचले लोगों को

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

अवसर मिले तो वे देश का भाग्य बदलने में अहम योगदान दे सकते हैं। दलितों में इंट्रप्रेनुरशिप बढ़ाने के लिए बैंकों को एक एक महिला और दलित को कम से कम एक एक करोड़ का लोन देना चाहिए। एससी/एसटी हब इसी दिशा में एक प्रयास है।

जेड योजना (जीरो डिफेक्टस, जीरो इफेक्ट्स) के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि अब सामान्य व्यक्ति खरीददार भी गुणवत्ता में समझौता करने को तैयार नहीं है। अगर देश की उत्तम सेवा करनी है तो हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए कि हम गुणवत्ता नियन्त्रण में वैश्विक मानकों को अपनाएंगे और दुनिया के मार्केट में हम अपना पैर जमाने के लिए भारत की पहचान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान तबाह हो गया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जापान खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनके छोटे-छोटे लघु उद्योगों ने गुणवत्ता में समझौता किए बिना मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कदम उठाए। हम लोगों को मालूम है, हम बाजार में कभी आज से कोई 15-20 साल पहले कोई चीज खरीदने जाते थे, और अगर उस पर लिखा है मेड इन जापान, तो हम कभी पूछते नहीं थे कि किस कंपनी ने बनाया, दाम पूछते थे, लेकर के चल देते थे क्योंकि भरोसा होता था कि एक गुणवत्ता में कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या हिन्दुस्तान की पहचान नहीं बन सकती दुनिया के किसी भी बाजार में, जैसे ही वो पढ़े 'मेक इन इंडिया' वो आंख बंद करके सोचेगा कि ये योग्य होगा, अच्छा होगा, किफायत भाव से बना होगा और वो लेने को तैयार हो जाए। ये सपना लेकर के हमें चलना है और इस सपना को पूरा करना है तो जीरो डिफेक्ट' उसकी पहली शर्त होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'जीरो इफ़ेक्ट, जीरो डिफेक्ट'

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

यानि जेड मार्का, उत्पादों में क्वालिटी स्तर बढ़ाने की योजना है। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ सके और 'मेक इन इंडिया' की धमक मज़बूत हो। इसका मतलब व मापदंड है कि उत्पाद जीरो डिफेक्टिव हो, वही ब्रांडिंग का आधार बनेगा।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने समारोह में 500 महिलाओं को चरखे प्रदान किया। उन्होंने उनके साथ चरखा भी चलाया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर महिलाएं बेहद प्रसन्न थीं। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने सबसे पहले प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज इस कार्यक्रम में लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री किसी योजना को लांच करने की दृष्टि से उपस्थित हुए हैं और प्रधानमंत्रीजी अपने करकमलों द्वारा लुधियाना में आज 500-500 करोड़ की दो योजनाएं– जेड प्रमाणन योजना(जीरो डिफेक्ट्स, जीरो इफेक्ट्स तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों हेतु राष्ट्रीय एस.सी.-एस.टी. हब योजना का शुभारंभ कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्तिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपके नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है।

मंत्री महोदय ने खादी पर बोलते हुए कहा कि खादी एक वस्त्र नहीं, विचार है। खादी को बढ़ावा देने के लिए लाल किले के प्राचीर से भी और मन की बात में भी प्रधान मंत्री जी द्वारा किये गये आव्हान पर गत दो वर्षों में खादी और खादी उत्पादों की बिक्री में लगातार 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगारों को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे खादी कारीगरों, कत्तिन और बुनकरों की आय में भी वृद्धि हुई है। पिछले 60 वर्षों में देश में 18 टूल रूम का निर्माण हुआ था। अगले दो वर्षों में हमारी सरकार का सहयोग तथा 2200 करोड़ रूपये के लागत से इनकी संख्या बढ़कर दुगुनी हो गयी है। इससे राष्ट्र में 5 लाख अतिरिक्त उद्योग कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने पिछले साल में पीएमईजीपी के अन्तर्गत 1.20 लाख उद्यमियों को 2692 करोड़ रूपए की सब्सिडी प्रदान की है, इससे करीब 9 लाख नये रोजगार के अवसर सृजन हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत राशि 5000 रूपए से कम करके 3000 रूपए कर दी गयी है और ब्याज की दर जो 11.50 %– 12.50 % भी सूक्ष्म उद्योगों के लिए 1 % कम किया जा रहा है। डिजिटल इण्डिया को डिजिटल रखते हुए मंत्रालय की सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।

श्री मिश्र ने कहा कि इस समारोह में आज, यहां राष्ट्रीय पुरस्कार, सूक्ष्म, लघु उद्यमियों को तथा खादी एवं कॉयर क्षेत्र में कार्य वाले 225 व्यक्तियों को दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री के करकमलों द्वारा पुरस्कार ग्रहण कर सभी का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य उद्यमियों को गुणवत्तायुक्त विनियोग किये जाने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त होगी। देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा स्वयं मंत्रालय को प्रगति की समीक्षा भी की गयी है, जिससे मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि हुई है।

इस अवसर पर मंत्री महोदय ने अपने सहयोगी मंत्रियों, अधिकारियों और उद्यमियों को धन्यवाद देते हुए पुरस्कार समारोह में विराजमान सभी लघु उद्यमियों, अन्य महानुभावों तथा पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देकर हृदय से आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एंव सशक्तिकरण राज्य मंत्री श्री विजय संपला ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्रीजी ने पूरे देश में उद्योग लगाने के लिए नौजवानों को प्रेरित किया है। Easy to doing Business में श्री कलराज मिश्र ने आनलाइन उद्योग आधारित मेमोरेन्डम जांच करके एक अभूतपूर्व कार्य किया है और उद्योग मेमोरंडम के तहत अब तक लगभग 16 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इतने रजिस्ट्रेशन अभी तक पिछले 50 वर्षों में भी नहीं हुए हैं। इस बात के लिए उन्होंने मंत्री महोदय को बधाई दी। अन्त में, उन्होंने प्रधानमंत्री, सभी सहभागी मंत्रियों, अधिकारियों और एवार्डी उद्यमियों का तहेदिल से समारोह में शामिल होने के लिए आभार प्रकट किया।

श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्य मंत्री पंजाब ने इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एमएसएमई पुरस्कार वितरण समारोह के लिए लुधियाना शहर को चुना है, जोकि पंजाब का दिल है जहां राज्य का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। लुधियाना शहर एमएसएमई क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बर्मिंगहैम जैसे शहर की तरह देश में सबसे बड़ा शहर माना जाता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आज पंजाब राज्य कृषि क्षेत्र में पिछड़ रहा है, यहां के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नयी पहल करें ताकि यहां के उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो सकें।

मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी का पंजाब के प्रति उनके लगाव के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत चार योजनाएं की शुरूआत करने के लिए पंजाब को चुना है। सबसे पहली योजना जोकि एससी एसटी हब बनाने की है जो कि एससी एसटी उद्यमियों को उद्योग लगाने में संरक्षण प्रदान करेगा। इस योजना के तहत इस वर्ग के उद्यमियों से 4 प्रतिशत खरीददारी सुनिश्चित की गई है. इस योजना का लोकार्पण पंजाब राज्य से किया जा रहा है, जहां देश में सबसे ज्यादा एससी एसटी की तादाद है. दूसरी योजना जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट है. यह योजना, देश में पारंपरिक कौशल के लिए जाना जाने वाला पंजाब राज्य, के कुशल उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी।

उन्होंने कहा कि, आज प्रधानमंत्री जी ने राज्य की 500 महिलाओं को चरखा वितरण किया है। यह कार्यक्रम, राज्य के हर घर में चरखे द्वारा महिलाओं के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों को चरखे के माध्यम से परिवार की आजीविका चलाने के लिए प्रोत्साहन देगा।

अंत में, केन्द्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री गिरिराज सिंह जी ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्रीजी के दिशा निर्देशन में खादी को आज विश्वस्तरीय स्थान मिला है। गांधीजी ने इसे स्वतंत्रता का माध्यम बनाया था, प्रधानमंत्री जी ने इसे अर्थ का माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एमएसएमई क्षेत्र ने ईजी डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत आज 18 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो आजादी के 70 साल बाद भी नहीं हुए थे, जोकि पिछले चार महिनों में हुए हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पंजाब के मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके दिशा निर्देशन में हमारे एफआईडीसी विभाग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में पंजाब राज्य में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

मंत्री महोदय ने अपने व्यस्ततम कार्यों से समय निकाल कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्य के महामहिम राज्यपाल, उप मुख्य मंत्री एवं मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद दिया।
इसके साथ ही उन्होंने, अपने अग्रणीय एमएसएमई मंत्री एवं आदरणीय राज्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके सानिध्य में एमएसएमई क्षेत्र आज नई उंचाईयों को छू रहा है। श्री सिंह ने केन्द्रीय मंत्री आदरणीय श्री विजय सांपला जी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने पूरी तन्मयता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है।

मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में खादी और कॉयर क्षेत्र मिल कर देश में पांच करोड़ लोगों को नये रोजगार देंगे।

समारोह में विराजमान सभी उद्यमियों, पुरस्कार विजेताओं और एमएसएमई मंत्रालय, खादी एवं कॉयर क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के भरसक प्रयासों से ही यह कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ है।

★★

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब का शुभारंभ

लुधियाना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लुधियाना में अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स की सहायता के लिए नेशनल एससी-एसटी हब का शुभारंभ है।

प्रधानमंत्री ने पुरस्कार समारोह में एमएसएमई की नई योजना -अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एससी-एसटी हब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इससे हमें उन दलितों उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता की भावना पैदा करने में फायदा होगा, जो युवा उद्यमों और रोजगार के अवसर पैदा करने का सपना संजोए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। "हमारा उद्देश्य वैश्विक बाजार को लक्षित करने के लिए होना चाहिए"। 490 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ, बाजार पहुंच /लिंकेजज, निगरानी, क्षमता निर्माण को मजबूत बनाने के लिए तथा वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की दिशा में काम करने के लिए, हब योजना का शुभारंभ किया गया।

एससी-एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देगी सरकार

यह हब पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों (सीपीएसई) को छोटे उद्योगों से न्यूनतम खरीद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के तहत मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई को अपनी कुल खरीद का 4 फीसदी अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमियों से खरीदना होगा। एमएसएमई सेक्टर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अहम है, जिसकी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 38 फीसदी हिस्सेदारी है और इसमें लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति हब खोलने की घोषणा की थी।

★★

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण का मूल पाठ

देश के कोने-कोने से आये हुए Micro-Industries के, लघु उद्योग से जुड़े भाईयों और बहनों,

सामान्य तौर से यह कहा जाता था कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है और होता भी ऐसा ही था। इतना बड़ा विशाल देश, लेकिन हर छोटे-मोटे काम दिल्ली में ही हुआ करते थे। हमने उस परंपरा को बदल दिया और हमारी कोशिश है कि कि दिल्ली के बाद भी, दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा हिन्दुस्तान है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अब दिल्ली दूरस्थ नहीं, दिल्ली समीपस्थ, दिल्ली पास है, यह अहसास है। पिछले दिनों भारत सरकार ने जितनी नई-नई योजनाओं को लागू किया, सभी योजनाएं हिन्दुस्तान के अलग-अलग केन्द्र में की गई। कभी कलकत्ता में, तो कभी रांची में, तो कभी रायपुर में, तो कभी भुवनेश्वर, तो कभी चेन्नई, कभी सोनीपत-हरियाणा। हर एक राज्य का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक शक्ति होती है और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि एक लुधियाना में लघु उद्योग क्षेत्र का एक लघु भारत आज मेरे सामने हैं। हिन्दुस्तान के हर कोने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां मौजूद हैं और मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी उद्योगकारों को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। वैसे आज जिनको सम्मानित होना है, उनकी संख्या करीब-करीब 250 की है क्योंकि कई वर्षों से ये पुरानी सरकारों ने भी काफी काम मेरे लिए बाकी रखे हुए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती उन सवा दो सौ-ढाई सौ विजेताओं को मैं स्वयं उनसे मिल पाता, उनको सम्मानित करता, उनको मिलने मात्र से उनकी थोड़ी ऊर्जा का लाभ मुझे भी मिल जाता, जो देश के काम आता। लेकिन समय की सीमाएं रहती है। और अगर ये 250 लोगों को देने का सिलसिला चलता तो यहां आधे लोग रह जाते। तो आयोजकों ने बताया कि हो सकेगा तो हर राज्य से एक-एक को प्रतिनिधि के रूप में आपके द्वारा ही किया जाएगा, बाद में मंत्रिपरिषद के द्वारा हर किसी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से आप सब को आपकी सफल यात्रा के लिए, आपकी भावी मंजिल के सपनों को प्राप्त करने के लिए अनेक-अनेक शुभकामनाएं हैं, सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, भारत के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने के लिए विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को बल देना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ताकत देना, ग्लोबल market को target करते हुए आगे बढ़ना, इस सुरेख सोच के

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

साथ भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।

मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आज विश्व की तेज गति से आगे बढ़नी वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आज बड़ी economy जिसको कहते हैं उसमें हिन्दुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली economy है, दो वर्ष आकाल होने के बावजूद भी। हमारा किसान परेशान था, कृषि उत्पादन में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी, उसके बावजूद भी manufacturing sector ने खासकर ये सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने एक कमाल करके दिखाया और भारत की विकास दर को न सिर्फ नीचे आने दिया, इतना ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान किया और उसका परिणाम यह है कि World Bank हो, IMF हो, Credit rating agencies हो, एक स्वर से सारी दुनिया कह रही है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक गतिविधि, जब पूरा विश्व 2008 की स्थिति में आ गया है, slow-down है, एक अकेला हिन्दुस्तान है जो दुनिया की economy को भी बल दे रहा है और उसके पीछे Manufacturing sector, Service sector का भी बहुत बड़ा योगदान है।

आज यहां तीन और प्रकार का भी मुझे अवसर मिला। सबसे पहले, पंजाब के गांव की माताएं-बहनें, टोकन स्वरूप 500 माताओं-बहनों को चरखा देने का मुझे आज अवसर मिला है और इन दिनों जो खादी पर हम बल दे रहे हैं, सूत के काम पर दाम बढ़ा रहे हैं, इन सबका नतीजा ये है कि जिस परिवार में एक चरखा है, करीब-करीब वो माताएं-बहनें, मैं सब माताओं-बहनों से बात कर रहा था, औसत 150 रुपए से ज्यादा per day उनकी कमाई हो रही है। एक प्रकार से गृह उद्योग के माध्यम से, खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और महात्मा गांधी का जो सपना था, अर्थव्यवस्था की इस नींव को भी मजबूत करने का, उसमें भी योगदान देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण काम खादी के द्वारा किया गया है। मैं बाद में उनके stall पर गया था। आपसे भी मेरा आग्रह है कि जरा देखिए। पहले जो हम सोचते थे, वो जमाना बदल चुका है आज खादी की quality देखिए, खादी का packaging देखिए, खादी ने corporate world को compete करे, उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और एक बात सही है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो खादी का अपना एक महत्व था। उस समय का मंत्र था, 'Khadi for Nation'. अब देश आजाद है। हमें आर्थिक क्रान्ति की ओर जाना है और इसलिए आज का मंत्र है, 'Khadi for Fashion'. आजादी के पहले जो 'Khadi for Nation', आजादी के बाद 'Khadi for Fashion'. अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव, गरीब, सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में, बदलाव लाने की एक ताकत रखता है और मैं लोगों से हमेशा आग्रह करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने। नीचे से ऊपर तक हर चीज खादी की हो, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। लेकिन आपके घर में पचासों प्रकार के fabric होते हैं तो कुछ खादी के भी तो fabric के item होने चाहिए। अगर हिन्दुस्तान के हर परिवार में कुछ न कुछ खादी का होगा और दिवाली के समय अगर हम कुछ न कुछ खादी खरीदते हैं तो गरीब के घर में दीवाली का दीया जलता है। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है?

आज मुझे उन सभी परिवारों की माताओं-बहनों का आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। आज एक और महत्वपूर्ण काम ये पंजाब की धरती से हो रहा है। और जब मैं पंजाब की धरती से कह रहा हूं तब उसका अपना एक महत्व भी है। इस समय हम जब गुरु गोविन्द सिंह जी के 350वीं जयंती मना रहे हैं और जब मैं आज पंजाब की धरती पर आया हूं तब, गुरु गोविन्द सिंह जी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्होंने एक बात जो कही थी, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। गुरु गोविन्द सिंह जी ने कहा था, 'मानस की जात सबई, एक पहचान वो'। मनुष्य की एक ही जात है, उसमें न ऊंच होता है, न नीच होता है; न स्पृश्य होता है, न अस्पृश्य होता है। गुरु गोविन्द सिंह जी ने उस कालखंड में जात-

पात, छूत-अछूत इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में हमारी विकृतियां आज भी हमारे दलित भाइयों के साथ कभी-कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, माथा शर्म से झुक जाता है। आजादी के 70 साल के बाद अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमें हमारी दिशा की धार और तेज करनी पड़ेगी, हमारे कार्य के व्याप्त को बदलना पड़ेगा, विस्तृत करना पड़ेगा। आदिवासी हो, दलित हो, जितने aspiration हिन्दुस्तान के अन्य नौजवानों में है, उससे भी बढ़कर aspiration आज मेरे दलित भाइयों-बहनों और मेरे आदिवासी भाइयों-बहनों के अंदर है। अगर उनको अवसर मिले तो भारत का भाग्य बदलने में, वे भी हमसे पीछे रहने वालों में से नहीं है। वो और ज्यादा योगदान कर सकते हैं।

हमारे देश में, हमारे मिलिन्द जी दलित समाज से है, स्वयं उद्योगार है। उन्होंने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया है। दलित समाज के entrepreneurs का Dalit Chamber of Commerce उन्होंने शुरू किया है। मुझे एक बार उनके समारोह में जाने का अवसर मिला। हिन्दुस्तान के top most entrepreneurs जो 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करते हैं, 1000 से ज्यादा बड़ी संख्या में, उसके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां मुझे कुछ माताएं-बहनें मिली, जो दलित परिवार से थीं, entrepreneur थी। उन्होंने कहा हमारी महिलाओं के संगठन में भी 300 से ज्यादा दलित entrepreneur महिलाओं का भी एक संगठन खड़ा हुआ है और वो 100 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार करती है। जब मैं उनसे मिला, तब मेरे मन में आया था कि इसको हमें एक और ताकत देनी चाहिए और ये जो schedule caste, schedule tribe, इसमें जो entrepreneurship है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आज यहां पर जो हमने पिछले बजट में घोषित किया था वो schedule caste, schedule tribe के entrepreneur के लिए एक Hub के निर्माण का, आज लुधियाना की धरती पर, पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। इससे जो दलित मेरे भाई-बहन है, जो आदिवासी मेरे भाई-बहन है, जो नौकरी पाने के लिए कतार में खड़े रहना नहीं चाहते। वे ऐसी जिन्दगी बनाना चाहते हैं, खुद भी किसी को नौकरी देने की ताकत पैदा करें। ये जिनका मिजाज है, सपना है, उनके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं।

बैंकों से कहा है, 'Start-up India, Stand-up India', इस कार्यक्रम के तहत हिन्दुस्तान में सवा लाख बैंकों के branches है, nationalised बैंक हैं। मैं और बैंकों की बात नहीं करता, cooperative वगैरह अलग। हर बैंक की branch एक महिला को, एक schedule caste को, एक schedule tribe को एक करोड़ रुपए तक की बैंक में से राशि दे और उनको entrepreneur बनाने के लिए मदद करें। देखते ही देखते सवा लाख branch पौने चार लाख ऐसे नए उद्योगकारों को जन्म दे सकती है। कितना बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया जा सकता है। हमारे दलित भाई-बहन जो manufacturing करेंगे, भारत सरकार जिन चीजों को procure करती है, हमने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है कि जो हमारे दलित और आदिवासी entrepreneur है, वे जो manufacturing करेंगे, चार प्रतिशत उनके यहां से लिया जाए ताकि उनको स्वाभाविक एक market मिले और उनका हौसला बुलंद हो, समाज के उन वर्गों को आर्थिक गतिविधि के केन्द्र में लाना है ताकि देश को एक नई आर्थिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए नई-नई शक्तियों का स्रोत हमें मिलता रहे, उस दिशा में काम करने का एक प्रयास इसके साथ चला है।

आज यहां एक और प्रकल का भी प्रारंभ हुआ है ZED. 'Zero effect Zero defect'. आप सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि अब सामान्य व्यक्ति खरीददार भी quality compromise करने को तैयार नहीं है। पहले हम भारत के ही market को देखते थे और सोचते थे कि ये चीजें हैं वो शहरी इलाकों में जरा पढ़-लिखे लोगों के बीच में बिक जाएगी, ये थोड़ी जरा finishing ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे उसको Tier II, Tier III शहरों में बेचेंगे और ये जो जरा और मामूली दिखती है उसको जरा गांव में जाएंगे तो बिक जाएगी। ज्यादातर हम लोगों की सोच भारत के ही market को ध्यान में रखकर के और आखिर ये इतना बड़ा देश है तो कोई product पड़ा तो रहता नहीं है, कोई garment बनाएगा, top quality का होगा तो बड़े शहर में जाएगा और थोड़ी हल्की quality का बन गया तो चलो भई गांव

के बाजार में रख देंगे चला जाएगा। अब वो वक्त नहीं है। सोच बदल रही है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि क्या हिन्दुस्तान का लघु उद्योगकार, क्या हिन्दुस्तान का सूक्ष्म उद्योगकार ये सिर्फ भारत के market को ध्यान में रखकर ही अपना कारोबार चलाएगा क्या। अगर देश की उत्तम सेवा करनी है तो हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए कि हम Quality control में global standard को अपनाएंगे और दुनिया के market में हम अपना पैर जमाने के लिए भारत की पहचान बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान तबाह हो गया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जापान खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनके छोटे-छोटे लघु उद्योगों ने quality में compromise किए बिना manufacturing sector में कदम उठाए। हम लोगों को मालूम है, हम बाजार में कभी आज से कोई 15-20 साल पहले कोई चीज खरीदने जाते थे, और अगर उस पर लिखा है made in Japan, तो हम कभी पूछते नहीं थे कि किस कंपनी ने बनाया, दाम पूछते थे, लेकर के चल देते थे क्योंकि भरोसा होता था कि एक quality में कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या हिन्दुस्तान की पहचान नहीं बन सकती दुनिया के किसी भी बाजार में, जैसे ही वो पढ़े make in India वो आंख बंद करके सोचेगा कि ये योग्य होगा, अच्छा होगा, किफायत भाव से बना होगा और वो लेने को तैयार हो जाए। ये dream लेकर के हमें चलना है और इस dream को पूरा करना है तो Zero defect उसकी पहली शर्त होगी। और कभी छोटी सी भी कमी, इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर एक नाविक नाव लेकर के जाना है उसको दरिया में, समुद्र में तो अपनी नाव को बराबर देखता है। छोटा सा भी छेद कहीं है तो नहीं, वो पक्का देखता है। कोई ये कहेगा कि इतनी बड़ी नाव है, कोने में एक छोटा छेद क्या है चिंता मत करो, चल पड़ो। नहीं जाता है। उसे मालूम है कि एक छोटा सा छेद भी उसको कभी वापिस आने में मदद नहीं करेगी, जिन्दगी वहीं पूरी हो जाएगी। manufacturing करने वाले के दिमाग में ये उदहारण रहना चाहिए कि Zero defect होगा तब जाकर के मैं दुनिया के अंदर अपनी ताकत पहुंचा पाऊंगा और इसलिए standardization, quality control और उसी से branding पैदा होता है।

Global market हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि भई हम तो एक छोटे से व्यक्ति है, छोटी सी मशीन है, तीन कामगार है- पांच कामगार है- दस कामगार है, हम क्या दुनिया देखेंगे। ऐसा मत सोचो। आज दुनिया में स्पेस के क्षेत्र में, सैटेलाइट की दुनिया में, दुनिया भारत का लोहा मानती है। हमने मार्स मिशन किया। हम मंगलयान में सफल हुए और दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही trial में मंगलयान में सफल हुआ। हमारे नौजवानों की बुद्धि, ताकत देखिए। कितने खर्चे में हुआ। लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद एक किमी. का 8-10 रुपए लग जाते होंगे। हमने मंगलयान तैयार किया। एक किमी. का सिर्फ 7 रुपए खर्च आए। इतना ही नहीं अमेरिका में हॉलिवुड की जो फिल्म बनती है, हॉलिवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, टैक्निशियनों ने मार्स मिशन का खर्चा, कम खर्चे में पूरा किया।

इतनी बड़ी सफलता, उसका अगर इतिहास देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज जो दुनिया में, स्पेस में हमारा नाम है। कभी ये स्पेस की दुनिया का कारोबार कहा होता था, बंगलूर की और हिन्दुस्तान की अलग-अलग जगह पर लोगों के motor garage की जो खाली जगह पड़ी रहती थी, उसमें दो-चार लोग मिलकर के इस काम को करते थे और कभी आपने प्रारंभिक दिनों की एक फोटो देखी होगी तो दो लोग साईकिल पर ये सैटेलाइट का एक part साईकिल पर बांधकर के, tow करके ले जा रहे है ताकि वो आसमान में जाना है। कोई कल्पना कर सकता है कि उस दिन जिसने देखा होगा कि साईकिल पर सैटेलाइट का पार्ट ले जाने वाला ये देश आज दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा लेता है। लघु उद्योगकारों के लिए, ये उनके मन में सपना रहना चाहिए कि भले आज हमारा product छोटा लगता होगा, मामूली लगता होगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने का in-built ताकत पड़ी हुई है, ये इसका एहसास करके अगर हम काम करते हैं तो हम उस ऊंचाइयों को पार कर

सकते हैं और उन सपनों को लेकर के चलना चाहिए।

जमाना बदल चुका है। जितना महत्व product का है, कभी-कभी लगता है कि उससे ज्यादा महत्व पैकेजिंग का हो गया है। कभी-कभी हमारा माल बहुत बढ़िया होता है लेकिन पैकेजिंग में कंजूसी के कारण हम मर जाते हैं। जब पंडित नेहरु जी की सरकार थी तो आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए एक कमीशन बैठा था और उस कमीशन का काम था कि आयुर्वेद हमारी traditional medicine है, वो खत्म होती जा रही है फिर से उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। उसको popular कैसे किया जाए तो एक हाथी कमीशन बैठा था, जयसुख लाल हाथी करके थे। उन्होंने उसकी रिपोर्ट दी थी। वो रिपोर्ट बड़ी पढ़ने जैसी है। उस रिपोर्ट के पहले पेज पर बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद को अगर बढ़ावा देना है तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये कागज की पुड़िया में जो आयुर्वेद देते हैं दुनिया में ये चलने वाला नहीं है। उसकी पैकेजिंग बदलनी चाहिए आयुर्वेद अपने आप दवाईयां बिकने लगेंगी। पहला सुझाव था उनका और मैं ये 60 की बात कर रहा हूं। आज तो हम जानते हैं कि पैकेजिंग का कितना महत्म्य बढ़ा है। हमने भी हमारी product के साथ पैकेजिंग को भी उतना ही महत्व देना होगा और जैसा देश। अगर हम जो देश अंग्रेजी नहीं जानते, अगर वहां हम अपना product हमारी पैकेजिंग पर अंग्रेजी में लिखकर के बेचेंगे तो कहा बिकने वाला है। आपको उसकी भाषा में पैकेजिंग बनवाना पड़ेगा। इसलिए हर चीज में Zero defect. इन दिनों इस ZED योजना के तहत एक बड़ा competition की कल्पना है। Bronze से लेकर के platinum तक पांच अलग-अलग layer के इनाम दिए जाएंगे और बड़े handsome prize दिए जाएंगे। कोई सीधा platinum नहीं पा सकेगा। पहले उसको नीचे के layer से पांच layer करते-करते उसको आगे बढ़ना होगा और उसको विशेष मान्यता मिलेगी। उस मान्यता के तहत दुनिया के बाजार में उसकी एक साख बनेगी। हमारी कोशिश है और मेरा उद्योगकारों को निमंत्रण है कि इस 'Zero defect Zero effect' movement में कम से कम 10 लाख उद्योग उस competition में आए आगे। 50 parameter तय किए है। उस 50 parameter के लिए अपने आप को सज्ज करे। कुछ कमियां हैं तो ठीक करे। आप देखिए Global market के लिए हमारे product जगह बनाना शुरू कर देंगे और भारत सरकार का यह प्रयास, यह सर्टिफिकेशन जो है वो दुनिया में काम आने वाला है। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण initiative आज यहां किया गया है।

Zero effect की बात जब मैं कर रहा हूं तब, दुनिया के देश, उनकी भी अपनी-अपनी एक रणनीति रहती है। अगर आपका माल दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है तो कभी किसी NGO के द्वारा एकाध आवाज उठ जाए कि दुनिया में से कि हिन्दुस्तान से फलां चीज आती है लेकिन वो तो environment को नुकसान करके manufacture होता है तो हम उस चीज का बहिष्कार कर देंगे। इतनी सी आवाज किसी ने उठा दी तो आपका माल उस देश में जाना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मानकर चलिए कि 5 साल-10 साल के भीतर-भीतर ऐसे कुछ लोग पैदा हो जाएंगे जो भारत की चीजों को अपने देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए environment नाम की चीजों को जोड़ देंगे। हमें अभी से तैयारी करे कि हमारी manufacturing से environment को zero effect होगा और Zero negative effect होगा। उस पर हम बल दे और डंके की चोट पर दुनिया को हम कहे कि हम वो चीज लेकर के विश्व में आए है जो मानव जाति के भाग्य को भी सुरक्षित रखती है, भविष्य को भी सुरक्षित रखती है और आपकी आवश्यकताओं की भी उत्तम से उत्तम पूर्ति कर सकती है। इसलिए 'Zero effect, Zero defect', इस मंत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं।

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है और मैं चाहता हूं किआप लोग इसका फायदा उठाएं। पहले भारत सरकार इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट देती थी, अवार्ड देती थी तो आप अपने चैम्बर में लटकाते थे। कोई आए तो उसको दिखाते थे लेकिन अब हम इसकी प्रतिष्ठा को और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं। भारत सरकार विधिवत रूप से आपको इस बात की अनुमति देती है कि आपको ये जो अवार्ड मिले हैं, आपको जो उसका एक logo मिला है, वे अब आपकी फैक्टरी में जो laborers है उनकी यूनिफॉर्म पर लगा सकते हैं। आप अगर अखबार में advertisement देते हैं, तो ये logo का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी मालिकी हो गई अब। इसके कारण आप उसके साथ गौरव अनुभव करेंगे। पहले इतने सारे बंधन थे आप इसका उपयोग नहीं कर पाते थे, हमने इसको relax करना तय कर लिया ताकि इसका आप भली-भांति उपयोग कर सके और इसके कारण जो आपका laborer होगा, जब उसके सीने पर वो लगा होगा तो वो कहेगा कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं जो अवार्ड winner कंपनी है और देश की विकास की यात्रा में इतना बड़ा contribute करने वाली कंपनी में मैं मुलाजिम हूं। वो भी एक शान का अनुभव करेगा। उस दिशा में भी काम करने की दिशा में हमने सोचा है।

अनेक ऐसे विषय हैं जैसे मैंने आपके सामने रखा, इन सारी योजनाओं का। आज लुधियाना की इस धरती पर नई गतिमिली है। मैं फिर एक बार manufacturing सेक्टर को बड़ा महत्व देता हूं।

Start-up पर हमारा बल है। मुद्रा योजना के द्वारा बैंकों से बड़ी मात्रा में छोटे-छोटे कारोबारियों को पैसा देने का काम किया है। आपको हैरानी होगी कि योजना को शुरू हुए अभी सवा डेढ़ साल हुआ है। डेढ़ साल में करीब-करीब साढ़े तीन-पौने चार

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

करोड़ कारोबारियों को दो लाख करोड़ रुपया, बैंक से without गारंटी पैसे दे दिए गए। वे नए रोजगार का निर्माण करने की ताकत रखते हैं और अच्छी बात यह है कि यह जो करीब पौने चार करोड़ लोगों को दो लाख करोड़ रुपया मिला है उसमें ज्यादातर करीब-करीब 70 प्रतिशत महिलाएं हैं, दलित, पिछड़ी जातिके लोग है। वे कुछ करना चाहते हैं। मुद्रा योजना के द्वारा उनको ये अवसर दिया गया है।

आज आपने देखा होगा कि उद्योगकारों के साथ-साथ हमने बैंकों को भी सम्मानित किया क्योंकिहम बैंकों को भी competition में लाना चाहते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्योग को कौन तेजी से पैसा देता है, कौन ज्यादा पैसा देता है, कौन ज्यादा मदद करता है, ऐसे बैंकों को भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ताकि बैंकों के बीच में भी लघु उद्योगकारों को पैसा देने का competition पैदा हो, उनके अंदर एक स्पर्धा चले और ज्यादा से ज्यादा इन छोटे उद्योगकारों को आर्थिक कठिनाई न आए, उसकी व्यवस्था खड़ी हो। ऐसे अनेक पहलू है। उन सभी पहलुओं को जोड़कर के भारत में छोटे-छोटे उद्योगों का एक बड़ा जाल निर्माण हो। हमारी जो नई पीढ़ी है वे साहस करना चाहती है, innovation करना चाहती है और ये बात सही है कि हम अब ये सोचे कि मेरी ये product मेरे दादा के जमाने से चलती थी तो अब भी चल जाएगी, तो ये होने वाला नहीं है। हर पीढ़ी को इनोवेशन के साथ नया product लाना पड़ेगा। छोटा उद्योग होगा तो भी innovation करते ही रहना होगा। Start-up innovation को बल देता है। talent को अवसर देता है। Start up में से लघु उद्योगों के लिए scale-up किया जाए, ऐसी अनेक नई चीजों के काम हो रहे हैं।

इन दिनों जो स्वच्छता का अभियान चला है। स्वच्छता के अभियान में भी एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार संभावित है। अगर हम स्वच्छता को आर्थिक दृष्टि से भी देखे तो waste में से wealth create करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं है। हम ऐसे tools बनाए, ऐसी मशीन बनाएं। अब जैसे आपने यहां एक प्रदर्शनी देखी होगी। पांच लाख रुपए की एक छोटी मशीन बना दी गई। पांच लाख रुपयों में वो फलों का essence निकालकर के fragrance वाली चीजें market में ला सकता है। अब गरीब व्यक्तिभी और मंदिर वाले भी। मंदिर के बाहर एक मशीन लगा दे तो मंदिर में जितने फूल चढ़ते हैं उसमें से बहुत बड़ी quality का इत्र तैयार करके बाजार में बेचा जा सकता है। कैसे ऐसी छोटी-छोटी मशीनें तैयार की जाए, सहज रूप से काम आने वाली मशीन कैसे तैयार की जाए। अगर हम इस प्रकार की innovation को बदलेंगे। Start up को बढ़ावा देंगे। आप देखिए हम लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग की दुनिया में बहुत बड़ा contribution कर सकते हैं।

मैं फिर एक बार कलराज जी और उनकी पूरी टीम को, उनके सभी मंत्रियों को, उनके विभाग के सभी अधिकारियों का हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तेज गतिसे गृह उद्योग से लेकर के लघु उद्योग तक, सारा ये जो पूरा holistic network है उसको बल देने का जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए विभाग के सभी अभिनंदन अधिकारी है।

मैं बादल साहब का भी बहुत-बहुत आभारी हूं किपंजाब सरकार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी परिश्रम किया। इसको यशस्वी बनाया और मैं बादल साहब ने मुझे भटिंडा के लिए याद कराया है, वैसे मुझे भटिंडा पहले जाना चाहिए था लेकिन समय अभाव से मैं जा नहीं पाया हूं। करीब एक हजार करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल भटिंडा में बनाने की भारत सरकार योजना है। लेकिन मैं वादा करता हूं बादल साहब आप तो हमारे सबसे बड़े सीनियर है। आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश होती है। मैं जरूर भटिंडा आउंगा जितना हो सके उतना जल्दी आऊंगा और एम्स के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। ★★

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र के भाषण का मूल पाठ

सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का बड़ा आभारी हूं कि आज इस कार्यक्रम में जिसमें लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया जा रहा है और साथ ही साथ यह पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री किसी योजना को लांच करने की दृष्टी से उपस्थित है और आज हमारी Zero defect-Zero effect योजना, SC/ST योजना लांच करेंगे। प्रधानमंत्रीजी अपने करकमलों द्वारा लुधियाना में आज 500-500 करोड़ की दो योजनाएं Zero defect-Zero effect योजना, National SC/ST Hub का शुभारंभ किया जाएगा। Zero defect-Zero effect का विचार सबसे पहले आपके द्वारा ही 15 अगस्त 2014 को लाल ाकिले के प्राचीर से उद्घोषित किया गया था। तत्पश्चात् Zero defect-Zero effect के 50 मानकों का निर्धारण क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इण्डिया द्वारा किया गया। इन मानकों के आधार पर Zero defect-Zero effect का प्रमाणन किया जायेगा। ZED को प्रेरणा देने तथा मूर्त रूप में शुभारंभ करने हेतु आपका आभार व्यक्त करता हूं।

समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्तिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपके नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। डॉ. बाबासाहेब के पांच प्रेरणा स्थलों के जीर्णोद्धारों को मूर्तरूप आपके करकमलों द्वारा किया जा रहा है। SC/ST के उत्थान से संबंधित योजनाओं के संपादन में सरकार के सभी मंत्रालयों के द्वारा अनेक योजनाएं प्रारम्भ की गयी है। इस क्रम में SC/ST वर्ग को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आपके करकमलों द्वारा National SC/ST Hub योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे SC/ST वर्ग उद्यमी भी उद्यमी भी सार्वजनिक खरीद में भागीदार बनेंगे।

राष्ट्रीय पुरस्कार, सूक्ष्म, लघु उद्यमियों को तथा खादी एवं कॉयर क्षेत्र में कार्य वाले 225 व्यक्तियों को दिये जा रहे हैं। आपके करकमलों के द्वारा पुरस्कार ग्रहण कर इन सभी का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य उद्यमियों को गुणवत्तायुक्त विनियोग किये जाने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त होगी। देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा स्वयं मंत्रालय को प्रगति की समीक्षा भी की गयी है, जिससे मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि हुई है।

खादी एक वस्त्र नहीं, विचार है। खादी को बढ़ावा देने के लिए लाल किले प्राचीर से भी और मन की बात में भी आपके द्वारा किये गये आव्हान पर गत दो वर्षों में खादी और खादी उत्पादों की बिक्री में लगातार 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिससे इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगारों को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे खादी कारीगरों, कत्तिन और बुनकरों की आय में भी वृद्धि हुई है। पिछले 60 वर्षों में देश में 18 टूल रूम का निर्माण हुआ था। अगले दो वर्षों में हमारी सरकार का सहयोग तथा 2200 करोड़ रूपये के लागत से इनकी संख्या बढ़कर दुगुनी हो गयी है। इससे राष्ट्र में 5 लाख अतिरिक्त उद्योग कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

हमारी सरकार ने पिछले साल में पीएमईजीपी के अन्तर्गत 1.20

लाख उद्यमियों को 2692 करोड़ रूपए की सब्सिडी प्रदान की है, इससे करीब 9 लाख नये रोजगार के अवसर सृजन हुए है। MSME के किसी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्रीजी की पहली बार शामिल होने पर मंत्रालय ने भी MSME उद्यमियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का निश्चय किया है। मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत राशि 5000 रूपए से कम करके 3000 रूपए कर दी गयी है और ब्याज की दर जो 11.50 % -12.50 % भी सूक्ष्म उद्योगों के लिए1 % कम किया जा रहा है। डिजिटल इण्डिया को डिजिटल रखते हुए मंत्रालय की सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने सहयोगी मंत्रियों, अधिकारियों और उद्यमियों की ओर से धन्यवाद देता हूं और यहां विराजमान सभी लघु उद्यमियों, अन्य महानुभावों तथा पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

★★

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

एमएसएमई पुरस्कार समारोह आयोजन की पूर्व संध्या पर प्रेस सम्मेलन

प्रधानमंत्री द्वारा एससी/एसटी हब और जेड स्कीम का उद्घाटन

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र और केन्द्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया।

श्री मिश्र ने संवाददाताओं को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री की विचार दृष्टि और बदलते भारत की उनकी कार्य योजना के अनुरूप पिछले ढाई वर्षों में एमएसएमई मंत्रालय ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मंत्रालय की एक प्रमुख योजना पीएमईजीपी यानि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की सम्पूर्ण कार्य प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार से 1,513 करोड़ रूपए की धनराशि दी गई है। इसमें पंजाब को इस वर्ष 47.42 करोड़ रूपए दिए गए हैं। हमारे मंत्रालय ने इस वर्ष 75,000 से अधिक उद्यमों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रख है, जिससे 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की आशा है। एमएसएमई मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने पहली बार वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए आवंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कुल 3400 करोड़ रूपए के बजट आवंटन में अभी तक 1900 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने नए टेक्नोलॉजी सेंटर (प्रौद्योगिकी केन्द्र) के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरूआत की है। नई सरकार के आगमन से पहले, 18 टेक्नोलॉजी सेंटर थे, जिसकी संख्या अगले वित्तीय वर्ष तक बढ़ाकर 36 की जा रही है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख औद्योगिक रूप से सक्षम कामगार मिल सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी केंद्र) 20 हजार से अधिक उद्योगों को प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

मंत्रालय की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है कैपिटल सब्सिडी स्कीम जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 15 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार वितरण समारोह

में अभी तक 215 करोड़ रूपए की धनराशि इस योजना में वितरित की जा चुकी है और मंत्रालय इस योजना में और 1000 करोड़ रूपए की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है।

एनएमसीपी योजनाओं के अंतगत मंत्रालय द्वारा देश में उद्यम गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें लीन मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम के प्रति उद्यमियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। पिछले दो वर्षों में लीन मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम से 2674 एमएसएमई लाभ उठा चुके है, जिनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक लाभांवित 241 एमएसएमई भी शामिल हैं। पंजाब में लीन मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम के अंतर्गत 1.00 करोड़ का निवेश किया गया है। डिजाइन क्लीनिक स्कीम के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में लगभग 600 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

कॉयर क्षेत्र में व्यापक संभावना दिख रही है। इसमें निर्यात बढ़कर 1900 करोड़ रूपए से भी अधिक हो गया है जबकि कुल उत्पादन 5 हजार करोड़ से भी बढ़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के साथ-साथ विभिन्न अवसरों पर खादी की चर्चा किए जाने से खादी की बिक्री बढ़ गई है और इसमें 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि देखी गई है। इन दोनो क्षेत्रों से अलग से 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। पीएमईजीपी के रोजगार सृजन को यदि हम इसमें मिला दें तो एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं से पिछले दो वर्षों में 20 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एमएसएमई क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से देश में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। यह बात इस तथ्य से समझी जा सकती है कि दिनांक 9 मई, 2007 को इस मंत्रालय के गठन के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री एमएसएमई मंत्रालय की किसी योजना की शुरूआत कर रहे हैं। श्री नरेन्द्र मोदीजी प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो एमएसएमई मंत्रालय की नई योजना का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री दो योजनाओं, जिनके नाम हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हब और जीरो डिफेक्ट एवं जीरो इफेक्ट यानि जेड स्कीम की शुरूआत पंजाब से कर रहे हैं। राष्ट्रीय एस.एसी./एस.टी.उद्यमियों की भागीदारी 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कराने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त, 2014 में की गई घोषणा के अनुरूप तैयार जेड स्कीम, जिसका पायलट आधार पर परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, के अन्तर्गत एमएसएमई मंत्रालय 22,000 से अधिक सूक्ष्म एवं लधु उद्यमों को सहायता प्रदान करेगा जिससे वे जेड सर्टिफिकेटशन प्राप्त कर सके।

चरखा हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और रोजगार का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात की भी सहमतिप्रदान की है कि वे पंजाब की महिलाओं के लिए 500 चरखे वितरित करेंगे। चरखा प्राप्त करने के बाद ये महिलाएं पंजाब के छह खादी संस्थान, जिनके नाम है - क्षेत्रीय पंजाब खादी मंडल (खरड़, मोहाली जिला), श्री गांधी खादी ग्रामोद्योग सदन (नाभा, पटियाला जिला), खादी सेवा सां (जालंधर जिला), सतलज खादी मंडल (नाकोदर, जालंधर जिला), आराध्य ग्राम समिति (बरनाला) और खादी ग्रामोद्योग कामगार सां (गोंसपुरा, संगरूर जिला) से जोड़ी जाएंगी। ये चरखा इन महिलाओं के लिए न सिर्फ जीवन-यापन का साधन बनेगा बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा आरंभ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी कराएगा।

संवाददाता सम्मेलन में श्री के.के. जालान, सचिव (एमएसएमई), भारत सरकार के साथ-साथ एमएसएमई मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

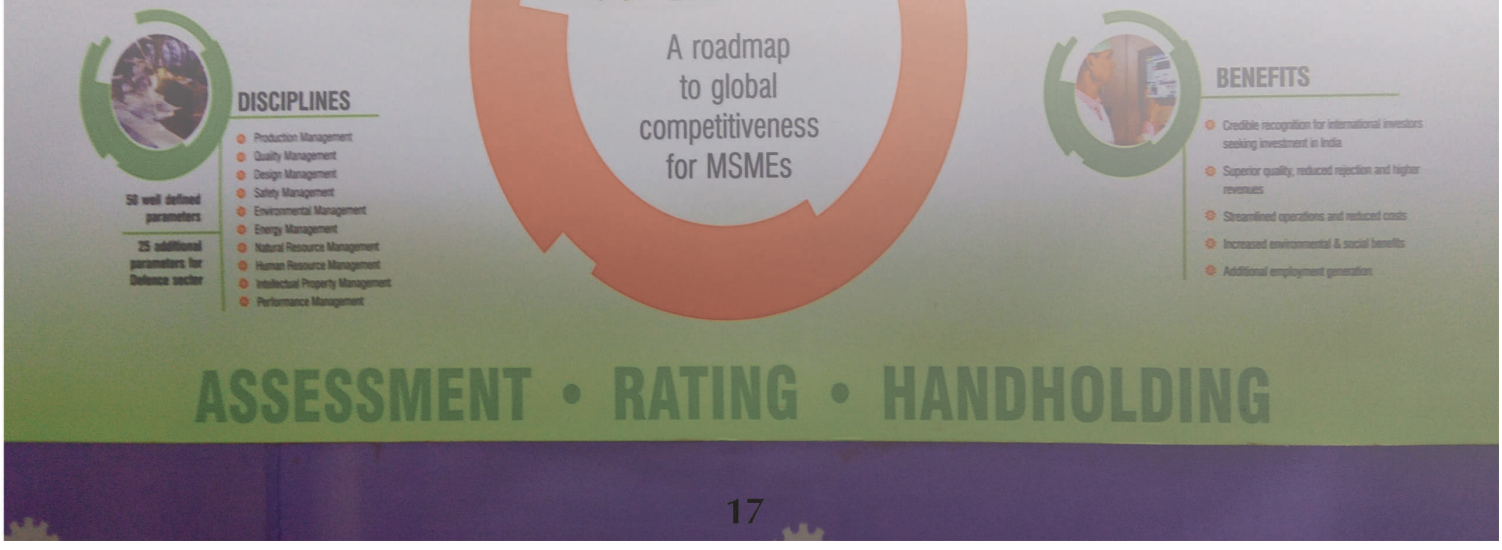

प्रधानमंत्री द्वारा 500 पारंपरिक काष्ठ चरखों का वितरण

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना में स्वतंत्रता सेनानी श्री के. कामराज द्वारा तमिलनाडु के पेरियार जो कि वर्तमान में मदुरै जिला है में सात दशक पहले 1945 में शुरू की गयी पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया।

तमिलनाडु के इस दिग्गज राष्ट्रीय नेता ने महात्मा गांधी के सुझाव पर तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में आयोजित एक कताई मेले के अवसर पर स्थानीय महिला कत्तिनों को 500 परंपरागत लकड़ी के चरखे दान स्वरूप दिये थे। उनके बाद किसी भी अन्य नेता ने इस तरह की पहल नहीं की।

वर्तमान में श्री कामराज के कदमों का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 5 स्थानीय खादी संस्थाओं से संबंधित 500 महिला कत्तिनों को 500 परंपरागत लकड़ी के चरखे वितरित किये। यह कताई मेला 18 अक्टूबर 2016 को लुधियाना, पंजाब में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार समारोह के हिस्से के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री वी.के. सक्सेना ने बोलते हुए कहा कि 500 महिला कत्तिनों को मोहाली, नाभा, नकोदर और पंजाब के गोनासपुरा गांवो से चुना गया है जिसमें से चालीस प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग से और छह प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। शेष सामान्य वर्ग की महिलाऐं हैं। 500 चरखे पहले ही लुधियाना पहुँच चुके है जो कि इन 500 ग्रामीणों को उनके द्वार पर प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेंगे।

श्री मोदी द्वारा प्रारंभ किये गए मेक इन इंडिया अभियान में चरखा वितरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, इसके अतिरिक्त चरखा वितरण ने समृद्ध गांधीवादी परंपरा को आगे बढाया है और इसे विश्व भर में काफी सराहा गया है. इस कार्यक्रम से देश में आत्म-निर्भरता, आत्म-जीविका और आत्म-योग्यता की भावना को भी बल मिलेगा।

★★

मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा खादी इंडिया आउटलेट का दौरा

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आयोग के नई दिल्ली स्थित खादी इंडिया आउटलेट का दौरा किया तथा आउटलेट में प्रदर्शित पर्यावरण अनुकूल खादी वस्त्रों की गुणवत्ता व आधुनिक परिधानों की सराहना की।

एमएसएमई राज्य मंत्री द्वारा खादी इंडिया आउटलेट का दौरा

केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आयोग के नई दिल्ली स्थित खादी इंडिया आउटलेट का दौरा किया तथा आउटलेट के पदाधिकारियों एवं उत्पाद डिज़ाइनरों से विचार विमर्श किया।

आयोग ने नई खादी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए शुरू की ऑनलाइन सेवा

गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पंजीकरण और नए खादी संस्थान के प्रमाण पत्र के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल **"खादी संस्था के पंजीकरण और प्रमाणन सेवा"** (KRICS) का शुभारंभ किया है । इस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुवात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र, द्वारा 2 अक्टूबर 2016 को खादी इण्डिया आउटलेट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में की गई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि **" नई खादी संस्थाओं के ऑनलाइन पंजीकरण की योजना से खादी और ग्रामोद्यगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित और विकसित करने, बढ़ावा देने, उनको सुविधाजनक बनाने तथा संगठित करने में सहायता होगी।"**

KRICS सुचारू रूप से व्यापार करने की दिशा में एक और कदम है। इस सुविधा के शुभारंभ के साथ, नई संस्थाओं के पंजीकरण और 40 दिनों के भीतर खादी और ग्रामोद्योग आयोग से खादी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगी। इस प्रक्रिया में पहले 3 वर्ष से अधिक का समय लगता था. 16 पृष्ठों के आवेदन फार्म को अब मात्र 1 पृष्ठ का कर दिया गया है. एक पृष्ठ के ऑनलाइन प्रारूप को भरने के बाद संस्था को एक विशिष्ट आईडी तुरंत प्राप्त होगी जिसके माध्यम से वे अपने आवेदन पत्र की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम हो जाएंगे। इस ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया की शुरूआत होने से इच्छुक संस्थानो को किसी भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय का दौरा किए बिना ही पंजीकरण और खादी प्रमाण पत्र समयबद्ध और बाधामुक्त तरीके से मिल जाएगा। श्री सक्सेना ने कहा कि खादी गतिविधियों में नए संस्थानो के शामिल होने से खादी क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार के अवसरों वृद्धि होगी।

श्री कलराज मिश्र ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह और श्री हरिभाई पर्थिभाई चौधरी की उपस्थिति में कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्थित खादी इंडिया शोरूम में विशेष वार्षिक खादी बिक्री अभियान शुरूवात की. इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना; सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री के.के. जालान, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधी, उद्यमी और पर्ल अकादमी के छात्रो ने भी अपनी उपस्तिथि दर्ज की। इस खादी बिक्री अभियान के तहत 20% छूट 60 दिनों तक सभी खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों पर दी जाएगी।

2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनायी जाएगी और इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह स्वच्छ भारत अभियान की शुरुवात करेंगे जो कि आयोग के देश भर में सभी कार्यालयों में अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा.

★★

आयोग का नए क्षेत्र में प्रवेश: बाल निरिक्षण गृह, दिल्ली में खादी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत

दिल्ली के आधारशिला बाल निरिक्षण गृह में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली के सेवा कुटीर में स्थित 'आधारशिला बाल निरिक्षण गृह' बंदा बहादुर मार्ग, किंग्सवे कैंप में खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण प्रारंभ कर एक नए दौर में प्रवेश किया है. यह बाल निरिक्षण गृह, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) द्वारा किशोर न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए बालकों के लिए चलाया जाता है.

इस खादी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 25 अक्टूबर, 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय

न्यायधीश श्री मदन बी. लोकुर द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना, डी.सी.पी.सी.आर. के अध्यक्ष श्री अरुण माथुर और एनसीपीसीआर, दिल्ली के अध्यक्ष श्रीमती स्तुति कक्कड़ की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए न्यायधीश श्री लोकुर ने कहा कि सामान्य अपराधों के लिए दोषी ठहराये गये युवा बालको को निरिक्षण गृह में कार्यकाल पूरा करने के दौरान सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करने का खादी और ग्रामोद्योग आयोग का यह प्रयास सराहनीय है।

श्रीमती कक्कड़ के अनुरोध पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने 10 नया मॉडल चरखा (एन.एम.सी.) और 2 करघे बाल निरिक्षण गृह को प्रदान किये तथा खादी कताई और बुनाई प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिससे इन बालको को रु. 150-200/- प्रति दिन अर्जन करने में मदद मिलेगी। चरखे और करघे बाल निरिक्षण गृह को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तीन महीने पहले ही प्रदान किये गये थे और यहाँ रह रहे बालको ने कताई और बुनाई का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया और इसमें काफी रूचि दिखाई। इस अवसर पर बोलते आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कताई ध्यान केन्द्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। कताई लोगों में आत्म अनुशासन की भावना को प्रबल करता है तथा इससे ध्यान केंद्रित करने मदद मिलती है और गलत आदतों की तरफ विचलन भी कम होता है। चरखा कताई से अशांत और क्षुब्ध मन भी शांत हो सकता है। "जब यह लड़के निरिक्षण गृह से बाहर जायेंगे तब वे प्रशिक्षित कत्तिन और बुनकर होंगे और पूरी गरिमा के साथ जीवन प्रारंभ करने में सक्षम होंगे।"

इस अवसर पर बोलते हुए एनसीपीसीआर की अध्यक्ष महोदय सुश्री स्तुति कक्कड़ ने बिना किसी शुल्क के चरखा और करघा प्रदान करने तथा दो महीने का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और कहा कि यह प्रयास लड़कों की मनोदृष्टि को बदलने में काफी सहायक होगा। श्री सक्सेना ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन युवा लड़कों को सार्थक प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि वे समाज में बेहतर ढंग से जीवन-यापन कर सके। ★★

मुंबई में खादी उत्सव 2016 का आयोजन

इस प्रदर्शनी में 237.13 करोड़ रु. की बिक्री चिन्हित की गई |

ग्रामोदय, 2 अक्टूबर 2016: खादी और ग्रामोद्योग आयोग के परिसर 'ग्रामोदय' मुंबई में क्रेताओं के लिए एक माह की अवधि की प्रदर्शनी 'खादी उत्सव 2016' का आयोजन किया गया। इस उत्सव में उत्कृष्ट खादी डिजाईनर वस्त्र, सुन्दर खादी रेशम की साड़ियां, हर्बल उत्पाद, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ, कुम्हारी उत्पाद, हस्तशिल्प, उत्कृष्ट काष्ठकरी, चर्म उत्पाद, अगरबत्ती, शहद, अचार, सांस्कृतिक हस्तशिल्प, और विभिन्न किस्म के कश्मीरी शाल जैसे – पश्मीना तथा शोजीनी इत्यादि प्रदर्शित की गयी जो कि भारत की बहुमूल्य संस्कृति को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त अन्य हस्तनिर्मित उत्पाद जैसे चादर, कुशन कवर, परदे, टेबलमेट्स, बैग, फर्निचर, चटाई, बक्से, केबिनेट, खिलौने, उद्यान के लिए गमले, टेराकोटा की आकर्षक सामग्रियां, पीतल और चांदी के उत्पाद, बांस और जूट से निर्मित सामग्रियां, कालीन, रग, दरिया इत्यादि की प्रदर्शनी में हाथो-हाथ बिक्री हुई|

यह प्रदर्शनी प्रत्येक वर्ष मुंबई मे आयोजित की जाती है और मुख्य रूप से इस प्रदर्शनी द्वारा उन कारीगरों, संस्थाओं और उद्यमियों को विपणन में समर्थन प्राप्त होता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं | इस वर्ष इस प्रदर्शनी में 237.13 करोड़ रु. की बिक्री चिन्हित की है|

इस प्रदर्शनी में गाँधी जी के साथ सेल्फी आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ था|

महात्मा गाँधी को श्रद्धांजलि

2 अक्तूबर, 2016 को आयोग के मुख्यालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों और अधिकारीयों ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को उनके 147 वी जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि अर्पित की | सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रमशः श्री के.एस.राव., श्री वाई.के. बारामतिकर और श्री एस.के. सिन्हा के साथ अन्य कर्मचारियों ने भी राष्ट्रपिता को श्रध्दा-सुमन अर्पित किये|

इस अवसर पर गाँधी जी के भजन 'वैष्णवजन तो तेने .....' का गायन किया गया और पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किये |

मुंबई में राज्य स्तरीय पीएमजीपी कार्यशाला

अहमदाबाद में खादी उत्सव-2016 का आयोजन

गुजरात राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अहमदाबाद एज्यूकेशन ग्राउन्ड, वस्त्रापुर, अहमदाबाद में खादी प्रदर्शनी 'खादी उत्सव 2016' का आयोजन 13 से 23 अक्टूबर 2016 तक किया गया।

इस प्रदर्शनी में गुजरात एवं अन्य प्रदेशों के पीएमइजीपी/आरइजीपी, खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री हेतु लगभग 250 स्टॉल लगायें गए थे. प्रदर्शनी का उदघाटन गुजरात सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं कुटिर उद्योग मंत्री श्री जयेश रादडिया के करकमलों से संपन्न हुआ।

इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री वासणभाई आहिर; आयुक्त, कुटिरेडा एवं ग्रामोद्योग, श्री एस.जे. हैदर; खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अहमदाबाद के राज्य निदेशक, श्री संजय हऊ आदि उपस्थित थे।

आयोग द्वारा ग्रीन चैनल के माध्यम से रेलवे को खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की आपूर्ति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दक्षिण रेलवे को ग्रीन चैनल प्रणाली के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की आपूर्ति करने की सहमती मिलने पर बहुत बड़ी जीत हासिल की है ।

दूसरे शब्दों में, आयोग अब अपने उत्पादों को गुणवत्ता का स्व-प्रमाण पत्र प्रदान करने में सक्षम है. आयोग अब अनुमोदित प्रयोगशालाओं जो मान्यता प्राप्त है अथवा राष्ट्रीय एक्क्रेदिशान बोर्ड के कैलिब्रेशन प्रयोगशाला (एन.ए.बी.एल), जो केंद्रीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत

स्वायतशासी निकाय है से परीक्षण के परिणाम के साथ अपने उत्पादों को स्व-प्रमाणित कर उनकी आपूर्ति कर सकता है|

अब तक, दक्षिण रेलवे ने इस पर जोर दिया था कि आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद डीजीएस और डीके जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारत का केंद्रीय खरीद संगठन है द्वारा गुणवता निरीक्षित होने चाहिए ।

दक्षिण रेलवे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री वी.के. सक्सेना द्वारा उल्लेखित ग्रीन चैनल प्रणाली का अनुपालन करने के लिए सहमत हो गयी है|

श्री सक्सेना के दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक, श्री वी. जोहरी को लिखे एक पत्र में इस बात पर जोर दिया कि किये गए अनुबंध में डीजीएस और डीके द्वारा निरीक्षण के कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है और अन्य सभी क्षेत्रीय रेलों में भी ग्रीन चैनल प्रणाली का ही अनुपालन किया जा रहा है|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र का विकास करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है एवं इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अर्जन के अवसरों में वृद्धि करना है | इस क्षेत्र में 1.8 करोड़ से अधिक व्यक्ति कार्यरत्त हैं|

इस क्षेत्र की महत्ता को महसूस करते हुए केंद्रीय सरकार ने, सरकारी विभागो और सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) इत्यादि में खादी उत्पादों को आरक्षित करने हेतु निति बनायी है | इसके आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्पादों के लिए डीजीएस और डीके के साथ संविदा दरों पर निर्णय लिया जायेगा|

पूर्व में बंगलुरु में 26 जुलाई 2017 को सरकारी आपूर्तियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी और इस बैठक में खादी और ग्रामोद्योग ने दक्षिण रेलवे को आपूर्ति के मुद्दे को उठाया जिसमे डीजीएस और डीके द्वारा गुणवता आश्वासन पर जोर दिया गया था और ग्रीन चैनल हेतु संविदा दर पर स्पष्टीकरण प्रदान किया

गया था| डीजीएस और डीके के निदेशक ने भी इस बैठक में भाग लिया और वे भी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रीन चैनल प्रणाली से सहमत थे और उन्होंने कहा कि दक्षिण रेलवे को डीजीएस और डीके गुणवता आश्वासन के लिए के लिए आयोग से आग्रह नहीं करना चाहिए|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न रेलवे को वृहद् मात्रा में चादरों की आपूर्ति करता है और प्रत्येक का पूर्व परिक्षण किया जाता है | इस प्रकार अतिरिक्त परिक्षण से उत्पाद की आपूर्ति करने में विलम्ब होगा तथा खादी संस्थाओं को अधिक परिक्षण लागत का भार वहन करना पड़ेगा| ★★

आयोग द्वारा किशोर अपराधियों को प्रशिक्षण देने के प्रयासों का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री एम.बी लोकुर ने, निरिक्षण गृह में रह रहे किशोर अपराधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों का स्वागत किया|

न्यायाधीश श्री एम.बी लोकुर ने उत्तर दिल्ली के किंग्सवे कैंप क्षेत्र में स्थित सेवा कुटीर में 'आधारशिला निरिक्षण गृह' में खादी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते समय यहाँ रहने वाले किशोरों को खादी की कताई और बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आयोग के प्रयासों की सराहना की|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस निरिक्षण गृह में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की और यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) द्वारा संचालित है जहां किशोर न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये बालको को रखा जाता है|

आयोग ने इस निरिक्षण गृह में निः शुल्क 10 नये मॉडल चरखे और दो करघे प्रदान किये है और यहाँ रह रहे किशोरो को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे प्रति दिन 150/- रु से 200 /-रु तक अर्जित कर सकते है|

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कताई योग एवं ध्यान केन्द्रित करने और स्व-अनुशासन बनाये रखने का सर्वोत्तम उपाय है तथा कताई के प्रयास से गलत विचारों की तरफ भी मन विचलित नहीं होता|

उन्होंने आगे कहा कि चरखा कताई करने से क्षुब्ध मन भी शांत होता है। जब यह किशोर निरिक्षण गृह से बाहर जायेंगे तब यह प्रशिक्षित कत्तिन और बुनकर होंगे और पूरी गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करने में सक्षम होंगे|

इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश श्री एम.बी लोकुर, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण माथुर एंव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा सुश्री स्तुति कक्कड़ भी उपस्थित थी|

★★

आयोग के अध्यक्ष द्वारा लोक जागृति सेवा संघ ट्रस्ट का दौरा

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने 12 अक्टूबर 2016 को अहमदाबाद स्थित 'लोक जागृति सेवा संघ ट्रस्ट' का दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अहमदाबाद के राज्य निदेशक, श्री संजय हेडाऊ भी उपस्थित थे. धोलका तालुका स्थित खादी संस्थाओं के साथ चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने इस वर्ष के अंत तक धोलका तालुका में 100 चरखों की आपूर्ति और बढाने का आग्रह किया । श्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा ने क्षेत्र में मधुमक्खी पालन उद्योग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की । राज्य निदेशक ने विषय पर चर्चा करते हुए शीघ्र ही धोलका-भाल क्षेत्र में मधुमक्खी पालन एवं अन्य उद्योगो की संभावनाओं पर सर्वेक्षण करवाकर प्रशिक्षण जागरूकता शिविर स्थापित करने का आश्वासन दिया।

★★

केरल में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा

आयोग के सदस्य, दक्षिण क्षेत्र श्री के. चन्द्रमौली, और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दक्षिण क्षेत्र श्री जी. गुरुप्रसन्ना ने खादी ग्रामोद्योग भवन, एर्नाकुलम में प्रदर्शित मसलिन कपड़े की संरचना एवं बनावट की पुष्टि करने हेतु भवन का दौरा किया। उनके साथ आयोग के राज्य निदेशक, तिरुवनंतपुरम श्री आई. जवाहर और सहायक निदेशक, त्रिवेंद्रम श्री सी.एम. गोपालकृष्णन भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर आयोग के सदस्य, दक्षिण क्षेत्र ने केरल में क्रियान्वित किये जा रहे खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा भी की।

★★

आयोग की दिनांक 28 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न

638वीं बैठक का कार्यवृत्त

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 28 अक्टूबर 2016 को मुंबई में सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई । उपरोक्त बैठक में आयोग के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: श्री जय प्रकाश तोमर, आंचलिक सदस्य (मध्य अंचल), श्री जी. चन्द्रमौलि, आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल), डॉ संगीता कुमारी, आंचलिक सदस्य (पूर्व अंचल), श्री नारायण सी. बोरकाटकी, आंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल), श्री अशोक भगत, विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास), श्रीमती ऊषा सुरेश, वित्तीय सलाहकार/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं आयोग के सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

बैठक की शुरुआत में विशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान एवं विकास) ने अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग को वर्तमान आयोग में सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण कर लेने हेतु बधाई दी तथा उनके ऊर्जावान व उदारवादी व्यक्तित्व/प्रयासों की भी सराहना की, जिससे खादी गतिविधियों को हमारे देश/समाज के विभिन्न वर्गों में एक नवीन व विशिष्ट पहचान मिली है। आज खादी का उपयोग न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में एक आवश्यक घरेलू वस्तु के रूप में किया जा रहा है।

आयोग के समक्ष कुछ अन्य सुझाव भी प्रस्तुत किए गए, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

- आयोग ने संशोधित बजट आंकलन वर्ष 2016-17 तथा बजट आंकलन वर्ष 2017-18 (योजनागत तथा गैर-योजनागत) के संबंध में बजट निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार कर इसे अनुमोदन प्रदान किया । आयोग ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया है कि स्वीकृत बजट के सापेक्ष बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण की स्थिति/आंकड़े केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, आयोग ने सभी राज्य/मंडलीय निदेशकों को परिलक्षित नवीनीकरण योजना सहित उपयोग के विवरण उपलब्ध कराने हेतु अविलंब पत्र जारी करने का निर्देश दिया। आगे, आयोग ने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विपणन) के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि बिक्री केंद्र के नवीनीकरण हेतु सरकार से प्राप्त रु. 2.50 करोड़ के कुल बजट को वास्तविक निधि की आवश्यकता के अनुसार 121 चिन्हित बिक्री केन्द्रों में अविलंब पुनः आवंटित किया जाएगा।

- आयोग ने कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में चरखा संग्रहालय संस्थापित करने एवं इसके अनुरक्षण के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग व नई दिल्ली नगर निगम के मध्य निष्पादित किए जाने वाले समझौता ज्ञापन पर विचार कर इसे अनुमोदन प्रदान किया।

- समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 4 के संबंध में आयोग ने संग्रहालय में आने वाले दर्शकों से विजिटिंग शुल्क के रूप में प्राप्त राजस्व के बंटवारे संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। राजस्व के बटवारे के संबंध में एनडीएमसी से बातचीत की जाएगी और उसके जानकारी आयोग के समक्ष रखी जाएगी।

- समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 11 के संबंध में आयोग ने इस बात को अनुमोदन प्रदान किया कि इस

संबंध में किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद एवं मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष, एनडीएमसी व अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग विवादित मुद्दे का निबटान आपसी सामंजस्य से करेंगे।

• परिवर्तन/परिवर्धन पर समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 8 के संबंध में, जहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि खर्च को अनिवार्य रूप से एनडीएमसी अथवा खाग्राआ द्वारा वहन किया जाएगा, क्योंकि यह दोनों पक्षों से संबन्धित है, आयोग ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है कि सिविल कंस्ट्रकशन संबंधी सभी खर्च एनडीएमसी द्वारा वहन किया जाएगा तथा चरखे से संबंधित मामले का वहन खाग्राआ द्वारा किया जाएगा। इसलिए अनुबंध में एक उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाएगा।

• समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 10 के संबंध में एनडीएमसी को यह पूर्ण अधिकार है कि वह आयोग को बिना किसी कारण बताए इस समझौता ज्ञापन को किसी भी समय समाप्त कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पहल वृहद रूप से जनहित में है, इसलिए इस संबंध में एनडीएमसी को संग्रहालय को बिना किसी कारण बताए बंद करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अतः आयोग ने एनडीएमसी के परामर्श से इस खंड में संशोधन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

• नवीन खादी संस्थाओं को केआरडीपी के अंतर्गत संशोधित चयन मानदंडों के अनुसार सीधी सुधार सहायता प्रदान करने पर विचार करने हेतु सुधार कार्यान्वयन प्रभाग निदेशालय का प्रस्ताव। आयोग ने नवीन खादी संस्थाओं को केआरडीपी के अंतर्गत संशोधित चयन मानदंडों के अनुसार सीधी सुधार सहायता प्रदान करने पर विचार करने हेतु सुधार कार्यान्वयन प्रभाग निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निम्न संशोधनों के साथ "नवीन खादी संस्था की परिभाषा" को अनुमोदन प्रदान किया:

• नवीन खादी संस्थाओं" की परिभाषा के बिन्दु संख्या ३ के अंतर्गत, आयोग ने शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसे अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-व्यावसायिक अर्हता सहित वस्त्र, विपणन तथा ग्रामोद्योग में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव रखने वाले उन व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी, जिन संस्थाओं के विगत 03 वर्षों के तुलन पत्रक से लाभ प्रदर्शित होता है।

(1) "नवीन खादी संस्थाओं" की परिभाषा के अंतर्गत, बिन्दु संख्या 4 के संबंध में आयोग ने शर्तों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जिसे अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- ऐसा कोई गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), जिसके कार्य क्षेत्र में कत्तीन और बुनकर हैं तथा वर्तमान में माल और सेवाओं का प्रसंस्करण कर रहा हो तथा उसे इस क्षेत्र में 03 वर्षों का अनुभव हो।

(2) "नयी खादी संस्थाओं" की परिभाषा के अंतर्गत बिन्दु संख्या 05 पर - आयोग ने शर्त में निम्नप्रकार संशोधित करने का निर्णय लिया, जिसे अब निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा:-डीआरडीए/नाबार्ड आदि से मान्यताप्राप्त कोई स्वयं साहायता समूह, जिसके न्यूनतम 100 सदस्य हों तथा किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत
हो।

(३) छठे बिन्दु के संबंध में – 'उस एनजीओ का स्वयं का अंशदान व इक्विटी सहभागिता होनी चाहिए' – आयोग ने इस खंड को समाप्त करने का निर्णय लिया।

• · आयोग ने टिप्पणी में यथा प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु "चयन संबंधी मानदंडों" भी को अनुमोदन प्रदान किया।

• <u>आयोग के विविध/स्व: प्रेरित निर्णय:</u>

• विपणन निदेशालय द्वारा सभी प्रदर्शनियों के कैलेंडर का अग्रिम रूप से प्रेषित करना

- आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) की टिप्पणी को नोट किया तथा वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी प्रदर्शनियों के कैलेंडर को अग्रिम रूप से प्रेषित करने का निर्देश दिया, जिससे कि संस्थाओं व पणधारियों को अपनी योजना तैयार करने में आसानी हो सकी।
- आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के इस सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जहां तक हो सके सभी प्रदर्शनियों का आयोजन नवंबर से जनवरी के मध्य किया जाना चाहिए।
- आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य (ग्रामीण विकास) की टिप्पणी का संज्ञान लिया कि आयोग को "खादी रेल यात्रा" आयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।

भुवनेश्वर में 29 अगस्त 2016 को आयोजित आयोग की 636 वीं बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई (एटीआर) पर चर्चा के उपरान्त उठे मुद्दे।

सीबीआरटीआई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पुणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने हेतु आयोग की नामंजूरी के संबंध में आयोग ने निर्देशित किया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को निर्णय के बारे में तुरंत अवगत कराया जाए।

(1) बंद पड़ी इकाइयों का हिसाब चुकता करने के संबंध में: पूरे देश भर में विभिन्न व्यापार इकाइयों का हिसाब चुकता करने/बंद करने के संबंध में आयोग ने गठित समिति को निर्देशित किया कि बंद पड़ी इकाइयों की कुल परिसंपत्ति, देनदारी, लेनदारी इत्यादि के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए तथा इसे बट्टे खाते में डालने हेतु आवश्यक आंकलित राशि को 15 नवंबर, 2016 तक तैयार कर लिया, ताकि इस संबंध में आगे निर्णय लेने हेतु मंत्रालय को अवगत कराया जा सके।

(2) प्रबंधक-II के रिक्त पद को अनारक्षित करना: ट्रेडिंग के अंतर्गत दिनांक 27.11.2013 से प्रबंधक-II के रिक्त पद को अनारक्षित किए जाने के संबंध में आयोग ने निर्णय लिया कि मामले को सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु लाया जाएगा जिससे कि रिक्त पद को उस समय तक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भर लिया जाए, जब तक कि उपयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते।

(3) सभी खादी और ग्रामोद्योगी कारीगरों को पहचान पत्र जारी करने का मामला: सभी खादी और ग्रामोद्योगी कारीगरों को पहचान पत्र जारी करने के संबंध में आयोग ने निर्णय लिया कि 'स्मार्ट पहचान पत्र' हथकरघा मंत्रालय और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के केआरडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत जारी पहचान पत्रों के समान ही होने चाहिए और यह चिकित्सीय स्वास्थ्य बीमा, आधार संख्या तथा अन्य लिंकेज पर आधारित होना चाहिए। इसलिए, आयोग ने निर्देशित किया कि इस संबंध में व्यापक अध्ययन किया जाए और केआरडीपी के अधीन 'स्मार्ट पहचान पत्र' के बारे में कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) राज्य कार्यालय, आंध्रप्रदेश को हैदराबाद से विजयावाड़ा स्थानांतरित करना:

1. राज्य कार्यालय, आंध्रप्रदेश को हैदराबाद से विजयावाड़ा स्थानांतरित किए जाने के मामले पर आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) के अवलोकनों को नोट किया कि चूंकि स्थानांतरण में कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं हो सकती है अतः मामले को प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आयोग को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण अंचल) से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया जिसमें हुबली में कार्यालय खोलने की बात कही गई है जिससे उस क्षेत्र की

लगभग 80 खादी संस्थाओं को लाभ मिल सकेगा। यह बताया गया कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हुबली कार्यालय द्वारा सृजित की जाने वाली आईआरजी भी शामिल है । इस संबंध में प्रस्ताव को वर्ष 2017-18 तक स्थगित रखने के लिए एक पत्र मंत्रालय को भेजा गया था।

3. आयोग ने यह भी नोट किया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा रु.60.00 करोड़ की राशि 10 खादी प्लाजाओं के निर्माण के लिए प्रदान की गयी है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस अवसर का लाभ लेते हुए खादी प्लाजा के कुछ हिस्से का उपयोग करते हुए हुबली जैसे स्थान में उप कार्यालय/मंडलीय कार्यालय की स्थापना कर सकता है, जहां खादी प्लाजा की स्थापना की संभावना है। इससे न केवल उस क्षेत्र की संस्थाओं को लाभ मिलेगा अपितु इससे आईआरजी भी सृजित होगी। ऐसे मामले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप कार्यालय/मंडलीय कार्यालय खोलने हेतु सरकार से कोई भी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आयोग ने आगे निर्णय लिया कि देश के विभिन्न स्थानों पर खादी प्लाजा खोलने हेतु समेकित प्रस्ताव, बजट आवंटन, खादी प्लाजाओं की संख्या को औचित्यों के साथ आयोग की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

5. आयोग ने अध्यक्ष के अवलोकनों पर सहमति दी कि मंत्रालय से एक बार पुनः सभी औचित्यों तथा एक समेकित प्रस्ताव के साथ संपर्क किया जाए, जिसमें किराए, अधोसंरचना,कर्मचारी स्थिति, स्थापना खर्च, रखरखाव, आईआरजी सृजन, संस्थाओं को लाभ इत्यादि, राज्य कार्यालय, आंध्र प्रदेश को हैदराबाद से विजयवाड़ा स्थानांतरित करने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता शामिल हो, जिसमें आंध्र प्रदेश के हाल ही में हुए बंटवारे के चलते कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

6. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के अवलोकनों को नोट किया कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ग्रामोद्योग को संवर्धित करने हेतु प्राथमिकता देनी होगी और इस संब में पर्याप्त बजट प्रावधान करने की जरूरत है। आयोग ने इसलिए निर्णय लिया कि ग्रामोद्योग हेतु एक व्यापक कार्ययोजना बनायी जाएगी तथा सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

7. आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के अवलोकनों को नोट किया कि प्रचलित अभ्यास के अनुसार ग्रामोद्योगी इकाइयों से, जिन्होंने स्वीकृत ऋण का पूर्णतया उपयोग किया है, केवल 4% की दर से ब्याज लिया जाना चाहिए, जबकि जिन संस्थाओं ने ऋण राशि का दुरूपयोग किया है, उन पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाना चाहिए । अतः आयोग ने, आयोग की ग्रामोद्योगी योजना के अंतर्गत अनुपयोगी राशि की वूसली तथा ऋण चूककर्ताओं पर दंडात्मक ब्याज लगाने संबंधी मामले पर ध्यान देने का निर्णय लिया।

8. आयोग ने विशेषज्ञ सदस्य)ग्रामीण विकासके अवलोकनों को नोट किया कि(ऐसे पोषणीय ग्रामोद्योगों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन किए जाने की जरूरत है, जिन्हें उन स्थानों पर स्थापित किया जा सके जहां (1) पर्याप्त रोजगार के अवसरों की संभावना हो और साथ ही साथ (2) आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो (3) स्थानीय तौर पर उत्पादों का विपणन किया जा सके और (4) उन अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान की जा सके जिनके पास ग्रामोद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने हेतु वांछित योग्यता और अनुभव हो। उक्त इकाइयों को गावों को सशक्त करने हेतु स्थानीय उत्पादों तथा स्थानीय उपभोग की गांधीवादी विचारधारा पर संचालित किया जाएगा।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

Surgical strikes no less than that of Israel's exploits: PM

Our Army As Good As Any In World: Modi

'My head hangs in shame over Dalit atrocities'

Prime Minister Narendra Modi interacts with the women after handing over charkhas to them in Ludhiana on Tuesday

अलग-अलग कार्यक्रमों में मोदी ने...

पहले वर्दी का किया गुणगान, फिर खादी के लिए छेड़ी तान

लुधियाना में महिलाओं संग चरखा चलाते प्रधानमंत्री

BARCA, CITY SET FOR CLASH TODAY

India will engage with Pakistan, not sure when, says foreign secy

S Jaishankar says targeted killings done earlier as well

At Mandi rally, Modi likens surgical strikes to Israeli ops

BADAL GOVT'S HOPES DASHED

Irom Sharmila floats politi...

Prime Minister Narendra Modi works on a *charkha* at a ceremony to distribute spinning wheels to women at the Punjab Agricultural University in Ludhiana on Tuesday. — PTI

पहले वर्दी का किया गुणगान, फिर खादी के लिए छेड़ी तान

लुधियाना में महिलाओं संग चरखा चलाते प्रधानमंत्री मोदी

भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सेना का गुणगान करते हुए उसकी कार्रवाई की इजरायली अभियानों से तुलना कर दी। मोदी ने कहा कि अभी तक हम इजरायली सेना के किस्से सुनते आए थे लेकिन भारतीय सैन्य बलों ने भी दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने पंजाब के लुधियाना में आयोजित सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में भी भाग लिया और लघु उद्योगों खासतौर से खादी का खूब महिमामंडन किया।

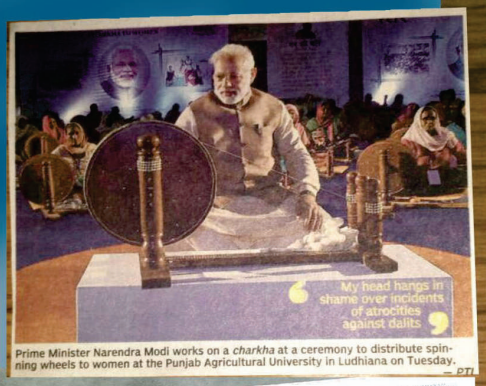

हिमाचल प्रदेश के मंडी में पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि देश भर में भारतीय सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, 'अतीत में हम यह सुना करते थे कि इजरायल ने ऐसा किया। अब पूरे देश ने देखा कि भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं।' इजरायल की सेना दुश्मन पर जवाबी हमले के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। बीते दिनों भोपाल में सैन्य स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेना बोलती नहीं बल्कि पराक्रम दिखाती है। सैन्य बलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पिछले 40 वर्षों से अधर में लटके 'वन रैंक, वन पेंशन' के वादे को पूरा किया। मोदी ने कहा कि अतीत में सरकारों ने इसके विश्लेषण की भी जहमत नहीं उठाई कि इस योजना को मूर्त रूप देने पर कितना खर्च आएगा। इस दौरान मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में परिवर्तन रैली को भी संबोधित किया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर निशाना साधा। मोदी ने इस पहाड़ी राज्य से अपने पुराने जुड़ाव को भी याद किया। भाजपा महासचिव के रूप में मोदी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं।

मोदी ने कहा कि अभी तक इजरायल के किस्से ही सुनते थे लेकिन भारतीय सेना ने भी दिखा दिया दम तो खादी पर कहा कि अब यह फैशन बन रही है

एससी एसटी उद्यमियों को सहायता

प्रधानमंत्री मोदी ने लुधियाना में आयोजित एमएसएमई के कार्यक्रम में कहा कि भारत मंदी के भंवर में फंसी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लघु उद्योगों का आह्वान किया कि वे 'जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट' यानी बिना किसी खामी वाले और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव वाले तरीकों से विनिर्माण कार्य करने की संस्कृति अपनाएं। मोदी ने देश में खादी उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस अवसर पर मोदी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी एवं एसटी) समुदाय के उद्यमियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र तथा एमएसएमई के लिए जेड प्रमाणन योजना की शुरूआत की।

उन्होंने कहा, 'आज हालात अलग हैं। देखना है कि खादी का विपणन कितने बेहतर ढंग से होता है। पहले 'खादी फोर नेशन' यानी देश के लिए खादी था अब 'खादी फोर फैशन' यानी फैशन के लिए खादी भी है।' प्रधानमंत्री ने लोगों से खादी के उत्पाद इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि यह भारत के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि घर में चरखा चलने से आमदनी होती है। एमएसएमई उद्यमियों से मोदी ने कहा, 'कम से कम 10 लाख इकाइयों को आगे आना चाहिए। हमने (जेईडी) प्रमाणन

ਦਸਮੇਸ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਸਰਵਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਕਵਰੀ ਮਰਗੇ

ਤ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ੈਂਡ

ਨਿਊ ਸਵੈਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

विश्व बाजार हमारा इंतजार कर रहा है, हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा उद्यम छोटा है: लुधियाना में एमएसएमई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री

Ludhiana an important economic centre: PM

Mohit.Behl@timesgroup.com

Ludhiana: On his maiden visit to Ludhiana after becoming the Prime Minister, Narendra Modi described the city as an important economic centre.

"Ludhiana is an important economic centre and it is natural to launch a scheme related to MSME here. I am seeing a mini-India in front of me," said Modi while addressing the gathering during the MSME award function here on Tuesday. Before distributing awards to 25 of the 225 winners, Modi said in a lighter vein, "I would love to give away awards to each one of the businessmen, but in that case more than half of the audience would leave the venue after getting bored."

Modi also took a jibe at the previous Congress government for keeping on hold award distribution for 2013-14. "I feel honoured to give away the awards. The previous government had kept this task pending for me," he said.

In his speech, Modi said the way India has become a world leader in space technology was nothing short of a miracle. "I still remember the days when satellite parts were carried on bicycles in South India and the country didn't have the required infrastructure, and the space labs used to be someone's backyard or garage in Bengaluru," he said.

While giving an example of how cost effective India's space expeditions are, Modi said the expenditure of the Mars mission was Rs 7 per kilometre, which was cheaper than the per kilometre fare of a three-wheeler in Ludhia-

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

The deceased has been identified as Harnek Singh, a resident of Gill village, here. Harnek, who worked as a labourer at a factory, was going to the workplace when the vehicle hit him.

The eyewitnesses said Harnek was on the right side of the road and was run over by a bus carrying policemen. The cyclist reportedly was crushed under the rear wheel of the bus.

The bus driver did not stop the bus and left the man in a pool of blood. He died on the spot later.

Meanwhile, the Dugri SHO, Joginder Singh, said it was not sure whether the bus involved in the accident

CONTINUED ON PAGE 3

the police at the accident spot on Gill Road in Ludhiana on Tuesday. TRIBUNE PHOTO: HIMANSHU MAHAJAN

the PAU grounds.

However, when the VVIPs had left the venue at around 4 pm, serpentine queues of vehicles were witnessed on one side of Ferozepur Road for about 10-15.

Raj Kumar, a school bus driver, said parents were

Industry hails Modi's vision, blames state for ta

SHIVANI BHAKOO

LUDHIANA, OCTOBER 18

Welcoming the vision of Prime Minister Narendra Modi, particularly the Zero Defect Zero Effect scheme which was highlighted by Modi at Punjab Agricultural University, the local industry maintains that for further growth in this competitive world, quality has to be maintained at any cost. At the same time, many of them condemned the state government for not providing benefits to the MSME sector at its own level. They said "bureaucracy" rules Punjab and it was not letting the industry grow.

The state secretary of the Punjab Pradesh Beopar Mandal, Mohinder Aggarwal, said Modi was undoubtedly right in highlighting the importance of quality management. "Unless and until we focus on quality management, we cannot compete with multinationals at the global level," he added. At the same time, Aggarwal said it was unfortunate that just two persons were chosen from Punjab for the awards.

"It is due to poor facilities provided to the MSME sector and tedious government procedures that the state industry is not growing at a fast pace. Chief Minister Parkash Singh Badal claim that power was cheaper for industry in Punjab than other states is absolutely wrong. We are paying huge amounts to get power because as all four thermal plants of the state are non-functional and power is being purchased from pri-

"We cannot depend entirely on the government machinery. We need to make best efforts from our side also. Skill is there, we need to use it properly."

MADAN MOHAN VYAS, YARN AND SPINNERS' ASSOCIATION

"The PM focused on quality, which is the key factor. We have to focus on bringing new innovations to compete with countries like China."

GURMEET SINGH KULAR, PRESIDENT, FICO

"Unless and until we focus on quality management, we cannot compete with multinationals at the global level."

MOHINDER AGGARWAL, STATE SECRETARY, PUNJAB PRADESH BEOPAR MANDAL

READE
Beginning

WHAT MODI DID IN INDUSTRIAL CITY

LAUNCHES NATIONAL SC/ST HUB

WHAT IS IT: With an initial outlay of ₹490 crore, the hub will provide professional services to SC/ST entrepreneurs.

PM TAKE: This will enable central public sector enterprises to fulfil the target of 4% of government's procuring goods manufactured by Dalits.

'ZERO DEFECT, ZERO EFFECT' CERTIFICATION

WHAT IS IT: This is the 'zero defect, zero effect' certification for entrepreneurs who will be judged on 50-point criteria to ensure quality without impacting the environment.

PM TAKE: A made-in-India product should be as good as Japanese products. You see the tag and know there has been no compromise with the quality.

TRIES HIS HANDS AT 'CHARKHA'

The Prime Minister gave away 500 traditional wooden charkhas to women spinners. "A 'charkha' can help the poorest of the poor to earn up to ₹250 a day," he said.

PRESENTS NATIONAL MSME AWARDS

Of the 250 awardees announced for innovation and manufacturing excellence, Modi honoured 27 of them. "I wish I could give away all the awards myself and gain energy from the awardees to use it for the nation," he said.

modispeak

During India's struggle for freedom, Khadi used to be for nation, now Khadi is for fashion. Buy a khadi product this Diwali, so that those who spin the 'charkha' can also celebrate the festival of lights.

Under the 'Startup India Scheme', 1.25-lakh branches of nationalised banks have been directed to sanction loans up to ₹1 crore to at least one woman, one SC and ST person.

Ludhiana is an important economic hub. It is only natural to launch a scheme related to MSME here. I am seeing a mini-India in front of me.

No enterprise is small. Some parts of our satellites are transported on bicycles before they are fitted in.

Can our MSME sector only keep looking at the market in India? No. Let us look at the global market and match their quality-control standards.

10/26/2016 Digital Edition

Ludhiana Tribune. 19 October 2016

(12)

Industry hails Modi's vision, blames state for tardy growth

SHIVANI BHAKOO
TRIBUNE NEWS SERVICE

LUDHIANA, OCTOBER 18

Welcoming the vision of Prime Minister Narendra Modi, particularly the Zero Defect Zero Effect scheme which was highlighted by Modi at Punjab Agricultural University, the local industry maintains that for further growth in this competitive world, quality has to be maintained at any cost. At the same time, many of them condemned the state government for not providing benefits to the MSME sector at its own level. They said "bureaucracy" rules Punjab and it was not letting the industry grow.

Punjab Pradesh Beopar Mandal, Mohinder Aggarwal, said Modi was undoubtedly right in highlighting the importance of quality management. "Unless and until we focus on quality management, we cannot compete with multinationals at the global level," he added. At the same time, Aggarwal said it was unfortunate that just two persons were chosen from Punjab for the awards.

"It is due to poor facilities provided to the MSME sector and tedious government procedures that the state industry is not growing at a fast pace. Chief Minister Parkash Singh Badal claim

"We cannot depend entirely on the government machinery. We need to make best efforts from our side also. Skill is there, we need to use it properly."

MADAN MOHAN VYAS, YARN AND SPINNERS' ASSOCIATION

"The PM focused on quality, which is the key factor. We have to focus on bringing new innovations to compete with countries like China."

GURMEET SINGH KULAR, PRESIDENT, FICO

"Unless and until we focus on quality management, we cannot compete with multinationals at the global level."

MOHINDER AGGARWAL, STATE SECRETARY, PUNJAB PRADESH BEOPAR MANDAL

industry in Punjab than other states is absolutely wrong. We are paying huge because as all four thermal plants of the state are non-functional and power is

vate companies," said Aggarwal.

A former chairman of the Ludhiana Improvement Trust and representative of the Yarn and Spinners' Association here, Madan Mohan Vyas, said the PM's vision was encouraging. Now, it is the duty of countrymen to implement it. "We cannot depend entirely on the government machinery. We need to make best efforts from our side also. There is a need to ignite the fire. Skill is there, we need to use it properly," said Vyas.

The president of the Federation of Industrial and Commercial Organisations

[redacted]

Like Tweet Share G+1

(13) Download

Jobs&Careers EVERY WEDNESDAY WITH The Tribune

The Tribune
VOICE OF THE PEOPLE
ESTABLISHED IN 1881
WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2016 ■ LATE CITY EDITION
CHANDIGARH | GURGAON | JALANDHAR | BATHINDA | JAMMU | SRINAGAR | WWW.TRIBUNEINDIA.COM | VOL. 136 NO. 290 | 32 PAGES | ₹4.50 | REGD. NO. CHD/0006/2

Wed Oct 19 2016 Subscribe Clip Page No. < Page 1 of 18 > [redacted]

'Like Israel does' spin to surgical strikes

PM says Indian Army 'no less than others' | Dedicates 3 hydel projects during HP visit

DIPENDER MANTA

MANDI, OCTOBER 18

Prime Minister Narendra Modi today equated the Indian Army's surgical strikes across the LoC with Israel's exploits. Speaking at his first public meeting in the state on becoming PM, he said the success of these strikes had proved to the world that the Indian forces were second to none.

"A strong signal has been sent out to the world that the Indian Army is no less than any other in prowess and ability... it is a proud moment not only for the Army but also for all ex-servicemen and countrymen and my salute to the Army for its valour and courage," the PM said.

He was here to dedicate to the people of the state three mega hydel power projects — Kol Dam (800 MW), Parbati Stage-3 (520 MW) and Rampur hydel project (412 MW).

Underscoring his commitment to the welfare of armed forces, Modi said his government had fulfilled its promise of one-rank, one-pension (OROP) scheme for ex-servicemen, an issue which had been "hanging fire" for over 40 years. The UPA, he pointed out, had failed to make adequate budgetary provision for the scheme. Himachal Pradesh has a sizeable population of ex-servicemen.

The PM blamed successive governments at the Centre for failure to complete projects. "I have had to create a cell in my office to trace buried files and give shape to pending projects," he said.

With a little over a year left for the HP Assembly elections, Modi hit out at Chief Minister Virbhadra Singh. "While Shanta Kumar and PK Dhumal are remembered for providing clean drinking water and improving the road network, do I need to mention what Virbhadra Singh will be remembered for," he remarked, an oblique reference to the corruption cases against the CM.

Prime Minister Narendra Modi at a ceremony to distribute charkhas before the MSME awards function at PAU in Ludhiana on Tuesday. PTI

Make khadi a fad: PM in Ludhiana

LUDHIANA: Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday that micro, small and medium enterprises (MSME) had a key role to play in transforming economy.

Modi, who was at Punjab Agricultural University to launch the SC/ST Hub and ZED (Zero Defect, Zero Effect) scheme, presented awards to 225 MSME entrepreneurs and gave away wooden charkhas to 500 women. He said the hub aims at promoting entrepreneurship among the SC/ST population and enabling the SC/ST-owned enterprises to participate more effectively in public procurement.

Addressing industrialists, he said khadi should be given a boost and SC/STs encouraged to turn entrepreneurs instead of being job-seekers. "Khadi for nation" was the mantra during the freedom struggle, he said, adding that "today, it must be khadi for fashion". He urged the people to buy at least one khadi item this Diwali. – Meena Zutshi

'Lin attac
Foreign S
NEW DELHI, O
The Army "target-spec tire, counter tions" across trol in the p for the first ment has go it, a parliam told today, appear to Defence Mi
Foreign S hankar gav tion to the Committee Affairs when cally asked surgical str done in the
"Professio get-specific, counter-ter have been c the LoC in t this is for th the governm public," acc present in t
The top d ments as sur the context Defence Mi Parrikar rej claims that

Littran woman to be awarded by PM

GAGANDEEP SINGH
TRIBUNE NEWS SERVICE

JALANDHAR, OCTOBER 17

For her contribution to popularising khadi spinning, Gurdev Kaur (60) from Littran village in the Nakodar sub-division has been selected to be honoured by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Ludhiana tomorrow.

She will be awarded a charkha (spinning wheel), a certificate and a memento. Gurdev Kaur left for Ludhiana today to participate in the practice session to be held at Punjab Agriculture University (PAU).

Speaking to Jalandhar Tribune, Gurdev's husband, Sohal Lal (65), said, "It has been more than 35 years that she has been spinning thread. She started alone with the charkha given to her as a gift by her parents during our marriage. Meanwhile, numerous other women from the village have been spinning thread out of the raw cotton provided by the Khadi Bhandar, Nakodar. She has spun hundreds of quintals of thread since then with charkha given by her mother."

He said apart from spinning thread, she efficiently performs household jobs like cooking and dusting.

"We had received the letter from Delhi regarding the same weeks ago. We only got to know about the honour when we a young man from the village read the letter to us. We just ignored the letter, considering it to be a normal communication," he added.

Sharing his happiness with Jalandhar Tribune, he said

CONTINUED ON PAGE 2

Gurdev Kaur (60) spins khadi on a charkha. A TRIBUNE PHOTO

समाचार पत्रों में प्रकाशित
खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

WEDNESDAY | 19 OCTOBER 2016 | LUDHIANA

LUDHIANA Tribune

EDUCATION: COLLEGES RESENT GOVT'S FAILURE TO RELEASE SCHOLARSHIP FUNDS — PAGE 2

DIST SCAN: WEDDING INVITE REVIVES CULTURE OF PUNJAB — PAGE 3

BMW CRASH: SURVIVOR'S DISAPPEARANCE RAISES QUESTIONS — PAGE 4

MAINLY CLEAR SKY 33.0° MAXIMUM 18.0° MINIMUM

Ludhiana Tribune. 19 October 2016

Industry hails Modi's vision, blames state for tardy growth

SHIVANI BHAKOO
TRIBUNE NEWS SERVICE

LUDHIANA, OCTOBER 18

Welcoming the vision of Prime Minister Narendra Modi, particularly the Zero Defect Zero Effect scheme which was highlighted by Modi at Punjab Agricultural University, the local industry maintains that for further growth in this competitive world, quality has to be maintained at any cost. At the same time, many of them condemned the state government for not providing benefits to the MSME sector at its own level. They said "bureaucracy" rules Punjab and it was not letting the industry grow.

The state secretary of the Punjab Pradesh Beopar Mandal, Mohinder Aggarwal, said Modi was undoubtedly right in highlighting the importance of quality management. "Unless and until we focus on quality management, we cannot compete with multinationals at the global level," he added. At the same time, Aggarwal said it was unfortunate that just two persons were chosen from Punjab for the awards.

"It is due to poor facilities provided to the MSME sector and tedious government procedures that the state industry is not growing at a fast pace. Chief Minister Parkash Singh Badal claim that power was cheaper for industry in Punjab than other states is absolutely wrong. We are paying huge amounts to g... because as all four thermal plants of the state are non-functional and power is ... from private companies," said Aggarwal.

A former chairman of the Ludhiana Improvement Trust and representative of the Yarn and Spinners' Association here, Madan Mohan Vyas, said the PM's vision was encouraging. Now, it is the duty of countrymen to implement it. "We cannot depend entirely on the government machinery. We need to make best efforts from our side also. There is a need to ignite the fire. Skill is there, we need to use it properly," said Vyas.

The president of the Federation of Industrial and Commercial Organisations

"We cannot depend entirely on the government machinery. We need to make best efforts from our side also. Skill is there, we need to use it properly."

MADAN MOHAN VYAS, YARN AND SPINNERS' ASSOCIATION

"The PM focused on quality, which is the key factor. We have to focus on bringing new innovations to compete with countries like China."

GURMEET SINGH KULAR, PRESIDENT, FICO

"Unless and until we focus on quality management, we cannot compete with multinationals at the global level."

MOHINDER AGGARWAL, STATE SECRETARY, PUNJAB PRADESH BEOPAR MANDAL

2 www.punjabkesari.in लुधियाना केसरी

केन्द्र ने विभिन्न राज्यों को 1513 करोड़ की धनराशि दी : कलराज मिश्र

सम्बोधित करते कलराज मिश्र, साथ हैं गिरिराज सिंह, हरिभाई पार्थीभाई चौधरी।

लुधियाना, 17 अक्तूबर (गुप्ता): केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने बताया कि मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है। वह आज यहां पी.ए.यू. में पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

मिश्र ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 में विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार से 1513 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। इसमें पंजाब को इस वर्ष 47.42 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्रालय ने इस वर्ष 75 हजार से अधिक उद्यमों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की आशा है। मंत्रालय ने पहली बार वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए आबंटित धन राशि के पूर्ण उपयोग का लक्ष्य हासिल कर लिया है, कुल 3400 करोड़ रुपए के बजट आबंटन में अभी तक 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मिश्र ने बताया कि टैक्नोलॉजी सैंटरों के निर्माण के लिए सरकार गंभीर है।

इन सैंटरों की संख्या 18 से बढ़ाकर 36 की जा रही है इसमें एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष 5 लाख सक्षम कारीगर मिल सकेंगे। यह सैंटर 20 हजार से अधिक उद्योगों को प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एम.एस.एम.ई. क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। 2007 को इस मंत्रालय के गठन के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की किसी योजना की शुरूआत कर रहे हैं। एस.सी. एस.टी. हब में और जीरो डिफैक्ट और जीरो इफैक्ट स्कीम की शुरूआत पंजाब से हो रही है। प्रधानमंत्री पंजाब की महिलाओं के 500 सोलर चरखे भी वितरित करेंगे।

केजरीवाल के गुजरात दौरे अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए : हरिभाई पार्थी

राजनीतिक सवालों से कनी काट गए मिश्र, बिहार पर खूब बोले गिरिराज

पत्रकार सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जहां राजनीतिक प्रश्नों से पूरी तरह कन्नी काट दी, वहीं उनके मंत्रालय के राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बिहार की नीतिश लालू सरकार पर जमकर हमले किए और इस सरकार को जंगल राज 2 का नाम देते हुए कहा कि इस सरकार में पुलिस अधिकारियों से फिरौती मांगी जा रही है, बिहार की सत्ता माफिया चला रहा है।

गिरिराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार की जनता को जो विकास का पैकेज देने का वायदा किया था, उसके तहत मधेपुरा व छपरा में 2 बड़ी रेल परियोजनाएं व सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित मंत्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी ने कहा कि गुजरात में भाजपा बेहद मजबूत होकर उभरी है। गुजरात में केजरीवाल के दौरे केवल अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए हो रहे हैं।

For a change, no traffic chaos during PM's visit

Industry hails Modi's vision...

Sampla lauds Modi for uplifting SCs, STs

समाचार पत्रों में प्रकाशित
खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

वर्ष 11 अंक 44
पृष्ठ 14+8=22
लुधियाना, बुधवार
19 अक्टूबर 2016
महानगर
मूल्य ₹ 2.50

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार
दैनिक जागरण

ताजा सर्वेक्षणों में हिलेरी की जीत पक्की 13

चंद्रोदय : 8:50 बजे

साइना आइओसी एथलीट आयोग की सदस्य बनीं 12

www.jagran.com
पंजाब • दिल्ली • उत्तर प्रदेश • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • बिहार • झारखंड • जम्मू-कश्मीर • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

चरखे दी घूक : खादी फार फैशन का नारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना में मंगलवार को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पुरस्कार वितरण समारोह से पूर्व महिलाओं को चरखा वितरित कर उनका हौसला बढ़ाया। एजेंसी

सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

रू. 5-00 పేజీలు 16+16
www.eenadu.net
..., Nizamabad, Khammam, Ongole, Mahaboobnagar, Chennai, Bengaluru, Mumbai, Delhi

మంగళవారం లూధియానాలోని పంజాబ్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన జాతీయ సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల పురస్కారాల ప్రదానోత్సవంలో చరఖా తిప్పుతున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

Prime Minister Narendra Modi works at a 'charkha' at Punjab Agricultural University in Ludhiana on Tuesday. PTI

At Mandi rally, Modi likens surgical strikes to Israeli ops

Gaurav Bisht
gaurav.bisht@hindustantimes.com

MANDI: Prime Minister Narendra Modi on Tuesday hailed the Indian Army for hitting militant bases in Pakistan occupied Kashmir, comparing the offensive to covert operations by Israeli forces.

This is the first time that the Prime Minister has publically spoken about the September 29 surgical strikes which have been followed by a political slugfest, with the opposition accusing the government of trying to derive political mileage out of a military operation.

"Our army's valour is being talked about across the country these days. We used to hear earlier that Israel has done this. The nation has seen that Indian Army is no less," Modi said at a public meeting in Himachal Pradesh's Mandi.

Israel's military and secret service are considered to be among the best in carrying out covert operations against militants in foreign territory and assets of "enemy states".

Modi paid his respects to serving and retired soldiers, many of whom were in the audience, referring to the hil[l] state as "Veer Bhumi" (land o[f] the brave). Himachal is one o[f] the states that send a signifi[-]cant number of young men to the army.

Modi also credited his government for resolving the issue of equalising pension payouts for retired soldiers, which he said were pending for 40 years.

CONTINUED ON PAGE 9

BADAL GOVT'S HOPES DASHED

LUDHIANA: With barely four months to go for Punjab assembly polls, Prime Minister Narendra Modi dashed all hopes of the SAD-BJP alliance government by promising nothing special for the state during his visit to Ludhiana on Tuesday for the launch of the National SC/ST Hub and give away national awards for micro small and medium entrepreneurs. P2

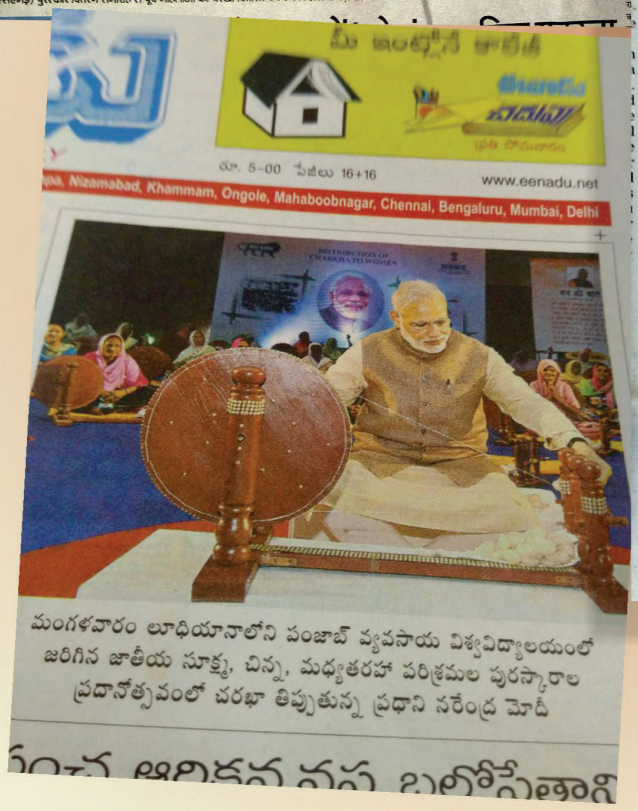

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

ਨਿਊ ਸਫੈਨ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ।

ਕਰਤਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਭਾਈ।

ਦਖ਼ਮੇਸ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਸਵਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ।

खादी देश के लिए और खादी फैशन के लिए : बापू को श्रद्धांजलि

श्री नरेंद्र मोदी ने खादी को लोकप्रिय बनाने और इसे एक जन आंदोलन का रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका आग्रह है कि सभी लोग खादी के सामान खरीदें, खासतौर से गांधी जयंती के दिन।

समाचार पत्रों में प्रकाशित
खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

अब ऑनलाइन होगा खादी संस्थानों का पंजीकरण

वैभव न्यूज ■ नई दिल्ली

गांधी जयंती के अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने नए खादी संस्थानों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए नए खादी संस्थान अपने पंजीकरण व प्रमाणन का काम आनलाइन करवा सकेंगे। आयोग का कहना है कि अब सारी प्रक्रिया में 40 दिन लगेंगे जबकि, पहले इसमें तीन साल तक का समय लग रहा था। इसी तरह आयोग ने 16 पन्ने के आवेदन फार्म को घटाकर एक पन्ने का कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री कलराज मिश्र ने यहां खादी इंडिया के बिक्री केंद्र पर 'खादी संस्थान पंजीकरण एवं प्रमाणन सेवा' पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तथा गृह राज्यमंत्री हरीभाई पर्थिभाई चौधरी भी मौजूद थे। महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर गिरिराज सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जोकि देश भर में खादी व ग्रामोद्योग कार्यालयों में सात दिन तक चलेगा।

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

NEW DELHI | MONDAY 3 OCTOBER 2016 | The Impressive Times
Nation 3

Khadi Commission to launched online Sewa for registration of New Khadi Institutions

Ajit kr. Pandey

NEW DELHI: On the occasion of Gandhi Jayanti today , Khadi & Village Industries Commission (KVIC) Launched an Online Portal namely "Khadi Institution Registration and Certification Sewa" (KRICS) for registration and certification of new Khadi Institution.

The online portal was launched by Shri Kalraj Mishra, Hon'ble Union Minister for MSME today 2nd October 2016 at 11.00 AM from Khadi India Outlet Connaught Place New Delhi. Shri V.K.Saxena, Chairman KVIC, Said that "The online Registration of new Khadi institution is necessary to plan, promote, facilitate, organize and assist in the establishment and development of Khadi & Village Industries in the rural areas".

The KRICS is another step towards ease of business.

Earlier this exercise was taking more than 3 Years. The old 16 pages application form has been reduced to just 1 page.

With the launch of this facility, the willing new Institution would be able to get their institution registered and will able to obtain the Khadi Certificate from KVIC within 40 days. Earlier this exercise was taking more than 3 Years.

The old 16 pages application form ... reduced to just 1 ... After ... online format, the institution will get Unique ID immediately, through which they will be able to track their applications status online. With the introduction of this online transparent process, the willing Institution will get the registration and Khadi Certificate in hassle ... bound manner ... office.

With the joining of new Institution in Khadi activity, the production and employment opportunities will increase in Khadi Sector "Saxena Said".

Shri Kalraj Mishra also started Special annual Khadi Sales Campaign from Khadi India Showroom in Connaught Place in presence of Shri Giriraj Singh and Shri Haribhai Parthibhai Chaudhary, Hon'ble Ministers of state for MSME, Shri V.K.Saxena, Chairman KVIC, Shri K.K. Jalan, Secretary, representatives of Khadi Institutions, entrepreneurs and Students of Pearl Academy. 20 % discount will be given on all products for 60 days.

2nd October being the birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, Shri Giriraj Singh also launched Swachchh Bharat Campaign which will continue in all KVIC offices across ... country for 7 days.

Soon, Centre-run hospitals to use khadi products

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Giving a push to the clarion call of Prime Minister Narendra Modi for promotion of khadi, Health Ministry has set up a high-level committee to look into how use of khadi can be promoted in hospitals under its control. Once the ministry chalks out the plan, khadi products would find their way into all Central government run hospitals across the country.

The Health Ministry has set up the panel following a meeting between Khadi and Village Industries Commission (KVIC) Chairman VK Saxena and Union Health Minister JP Nadda last week. During the meeting, Saxena made a request for measures to promote the use of khadi in the hospitals run by the Union Health Ministry.

The ministry has appointed Directorate General of Health Services' Special Director General BD Athani as chairman of the committee. The other members in the panel include AIIMS director, medical superintendents of Safdarjung Hospital and Ram Manohar Lohia Hospital and Director of Lady Hardinge Medical College and Associated Hospitals.

"The committee will submit its recommendations and suggestions in a time bound manner. The order setting up the panel was issued on September 22. The meeting between the minister and KVIC chairman took place on September 20," an official release said. The KVIC has been taking several measures to promote use of khadi products in the country and abroad ever since Saxena took charge of the commission in October 2015.

Now, registration of khadi institutions a click away

Union Minister for MSME Kalraj Mishra, Minister of State for Home Haribhai Parthibhai Chaudhary and KVIC Chairman V K Saxena at Khadi India outlet in New Delhi on Sunday PIC/NAVEEN SHARMA

MPOST BUREAU

NEW DELHI: Marking the Gandhi Jayanti, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) launched a portal for registration and certification of new khadi institutions, saying the entire process will now be completed within 40 days instead of up to 3 years earlier.

Also, the old 16-page application form has been reduced to just one.

The online portal "Khadi Institution Registration and Certification Sewa" (KRICS) was launched by Union Minister for MSME Kalraj Mishra at Khadi India outlet here.

Besides Mishra, Union Minister Giriraj Singh and Minister of State for Home Haribhai Parthibhai Chaudhary was also present on the occasion.

On the occasion of birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, Giriraj Singh also launched Swachchh Bharat Campaign which will continue in all Khadi and Village Industries Commission (KVIC) offices across the country for seven days.

"The online registration of new khadi institution is necessary to plan, promote, facilitate, organise and assist in the establishment and development of khadi and village industries in rural areas," KVIC Chairman V K Saxena said in a statement.

He said the portal will help in promoting ease of business for MSME units.

New institutions would be able get their registration and certification within 40 days, after uploading the required documents, Saxena said, adding earlier this exercise was taking more than 3 years.

PICKING UP THE THREADS: Prime Minister Narendra Modi at an event to promote the khadi industry. Spinning wh... distributed at the event in Punjab Agricultural University, Ludhiana, on Tuesday. — PHOTO: PTI

समाचार पत्रों में प्रकाशित
खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्यालय, मुंबई में14 सितम्बर को मोहित जैन, मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री के. एस राव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री वाई. के बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसके सिन्हा, राजभाषा अधिकारी/उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयोग के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी-गण उपस्थित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने दीप प्रज्ज्वलित कर हिन्दी पखवाड़े का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी से जुड़े विविध विषयों पर अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए तथा अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने की अपील की।

8 Friday 23 to 29 Sept. 2016 **Bharat Satya** Mission "Each House, A Girl"

Hindi Pakhwada organised at KVIC

लिज्जत से खादी ग्रामोद्योग की पहचान

षणमुखानंद में सर्वसाधरण सभा आयोजित

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ संस्था की 51 वीं वार्षिक सर्वसाधरण सभा षणमुखानंद सभागृह में संपन्न हुई. सभा का उद्घाटन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किया. सक्सेना ने कहा कि 50 वर्ष पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ महिलाओं को रोजगार देने वाला प्रमुख केंद्र बन गया है.

लिज्जत की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खादी ग्रामोद्योग को आज लिज्जत के नाम से जाना जाता है. 7 बहनों द्वारा शुरू की गई इस संस्था में आज 45 हजार से अधिक लोग कार्यरत हैं. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला द्वारा शुरू किया गया उद्योग महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदहारण है. कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा सुरेश और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाय. के. बारामतीकर भी उपस्थित थे.

केंद्र के अस्पतालों में खादी को बढ़ावा देने लिए पैनल का गठन किया

-रजनी पंवार-

नई दिल्ली। खादी उत्पादों को जल्द ही देश में केन्द्र सरकार चलाने के अस्पतालों में जगह मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने नियंत्रण केअस्पतालों में कैसे खादी के उपयोग को बढ़ाया जा सकता है इस पर गौर करने के लिए के एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। मंत्रालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, वी.के.सक्सेना , और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जे .पी .नड्डा , के बीच पिछले सप्ताह हुई एक बैठक के बाद पैनल का गठन किया है। बैठक के दौरान श्री सक्सेना ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित अस्पतालों में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के उपायों के लिए एक अनुरोध किया। विशेष महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, बी .डी.अथनि , समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल और निदेशक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पतालों के निदेशक हैं। यह समिति एक निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

Central Govt-run hospitals to have khadi products soon

PNS ■ NEW DELHI

Khadi products may soon find their way into Central Government-run hospitals in the country. The Union Health Ministry has set up a high-level committee to look into how the indigenous natural fabric can be promoted in its hospitals.

The setting up of the panel followed a meeting between Chairman of Khadi and Village Industries Commission VK Saxena and Union Health Minister JP Nadda, last week. During the meeting, Saxena made a request for measures to promote the use of Khadi in the hospitals run by the Central Ministry, said a senior official from the KVIC.

Headed by Special Director General, Directorate General of Health Services, BD Athani, the panel has members including director of All India Institute of Medical Sciences, medical superintendents of Safdarjung Hospital and Ram Manohar Lohia Hospital and director of Lady Hardinge Medical College and associated hospitals.

When asked about the agenda of the meeting, Athani said that panel members were yet to hold the first meeting to chalk out the plans. The panel will submit its recommendations and suggestions in a time bound manner, the official added.

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियां..

EMBRACING KHADI

Zero carbon footprint, sustainable, zero wastage, green. An age-old concept like khadi embodies all these new-age terms, making it all the more relevant today. The good news is, khadi is making a comeback like never before. Ivinder Gill explores how

WHEN MAHATMA Gandhi encouraged the use of khadi, it was to promote the ideology that Indians could be self-reliant on cotton and be free from foreign cloth and clothing. It was also a movement towards rural self-employment and self-reliance. We have since achieved freedom from foreign rule, but the economic freedom that a fabric like khadi can bring about is as relevant today, as it was before independence.

Moreover, khadi effortlessly achieves what brands and companies vie hard for—sustainability. Not many would know that khadi is a zero carbon-footprint fabric, needing no electricity or machines, or any kind of fuel for its manufacture. A simple comparison of numbers—3 litres of water to produce one metre of khadi versus 55 litres for one metre in a mill—is enough to give anyone an idea of the eco-friendliness of the fabric.

But all this is nothing new, except the fact that an idea that embodied economic and political freedom and sustainability somehow got lost over the years, especially after India took giant leaps of liberalisation. Global merchandise became more accessible and shone brighter, while homegrown ideas grew paler. This included khadi.

In recent years, as rapid industrialisation and greedy consumerism started showing their darker side,

0 CARBON FOOTPRINT FOR KHADI

3 LITRES OF WATER TO MAKE 1 METRE OF KHADI

LITRES OF

INTERVIEW: VK SAXENA | CHAIRMAN, KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION

'Sales up by 30% in past 10 months'

THE KHADI and Village Industries Commission is the agency at the forefront of the manufacture, sales and promotion of khadi in India. Its chairman **Vinai Kumar Saxena** *tells* **Ivinder Gill** *about the new initiatives that are giving a fillip to the production and image of khadi. Edited excerpts:*

Khadi Udyog has always been seen as an agency with *desi*, uncool stuff. But that's changing now. You are stocking jeans in your showrooms, have roped in Ritu Beri to design for you, have orders worth crores for your products. What is the thought behind this recent change?
If you really want to survive in the market, you have to be modern. You have to be competitive. We have to be right there with the others. Earlier, we were banking on the Khadi name, but now things have changed. The price competitiveness, the quality—these are the parameters we are accommodating. We are even participating in the tenders process, which was not done earlier, and are taking orders based on that.

Is there a specific plan to take Khadi as a brand or symbol to make it relevant in modern times?
Khadi can be called our national fabric. Unfortunately, the plus points of khadi have never been projected. For example, khadi has zero carbon footprint, which is very relevant in today's time. It is the most environment-friendly fabric. There's no need for electricity or any machines or fuel to make khadi. It is called an 'air-conditioned' material because in winters, it's warm and in summers, it keeps you cool because it is porous, handspun and handwoven. These qualities were never projected. But we are trying to change that with our awareness campaigns.

We installed the world's biggest *charkha* at Terminal 3 at the international airport in Delhi. It serves as a memorial for khadi artisans who have contributed to the nation, and not just in the freedom struggle.

People have also started supporting khadi not as part of charity, but as a fabric they want to wear, which is really important. Moreover, khadi has the power to provide employment in the remotest areas of the country. And we are doing our best to promote this. Gandhiji had said that the *charkha* will be useful even after independence. This is so true. With minimum expenditure, one can earn with respect. That is the power of the *charkha*. It requires no infrastructure, no formal qualification and there's no age bar. I have seen an 82-year-old woman in Saharanpur earning ₹100-₹150 a day weaving khadi. The *charkha* can be a tool for economic independence.

You have tied up with Air India and Indian Railways already. Any other agencies that have given you big orders?
From Railways, we got an order worth ₹40 crore and, from Air India, we got an order worth ₹11 crore to supply amenity kits for first-class and business-class passengers.

'PEOPLE HAVE STARTED SUPPORTING KHADI NOT AS PART OF CHARITY, BUT AS A FABRIC THEY WANT TO WEAR, WHICH IS REALLY IMPORTANT'

NTPC has given an order to supply 23,000 silk jackets worth ₹5.5 crore. JK Cement has gone completely khadi. All employees at its plants, schools, colleges and hospitals wear khadi. We have opened outlets at the Income Tax Bhavan in Mumbai, where there are 5,000 employees just for khadi.

The Prime Minister's Office buys file covers from us. The uniform of their staff is also supplied by us.

Is this plan to promote khadi a sustained, long-term model?
Definitely. The basic aim is to create employment, not generate profit. Our success lies in creating employment. And how will employment be created? When the sales will go up, naturally the production will go up. When the production is up, the artisans will get more work hours. So it's a chain. That's why we are focusing on marketing. Fortunately, the government is also very positive. The reason behind the Prime Minister's vision is that we should generate employment in rural areas.

So if you were to define the KVIC's goals, is it to promote and keep khadi relevant or generate employment. Or both?
It is both. Khadi has sentimental value also; it has participated in the freedom struggle. At the same time, it has the power to generate employment. That's why it has a different value. I want to connect people from two angles. This is a fabric that has participated in the national freedom struggle and now, by buying this fabric, you are supporting the rural artisans.

We see big swanky Khadi showrooms in metros and big cities. But what about smaller cities where they still look very dull?
We have reserved ₹50 crore this year to modernise khadi outlets across the country. And we have seen that once the store is modernised and made air-conditioned, sales go up manifold. But we can't modernise in a day. We have 7,060 outlets across the country. It is a huge organisation. It will take some time.

What about the franchise model?
We are launching franchises very soon. We advertised for it and have shortlisted 14 candidates and, I think, they will get franchises in a month or so.

You have roped in Ritu Beri to design for you. Are you planning to rope in more designers?
This is another way to popularise khadi. W[e] have recently launched her collection, Vichar Vastra, and it's selling like hotcake[s]. The fabric is provided by us, and the design[...] ing, dyeing, accessories, etc, are done by h[er].

We already have 45 designers on our pa[n]el. They are also designing and supplying [to] the KVIC. But when we rope in a person l[ike] Ritu Beri, things get a different fillip.

Are you also planning to rope in cele[bri]ty brand ambassadors?
Vichar Vastra has been worn by many prominent people. Film stars have also requested and they have agreed. The process is going on.

Transcribed by Nitin Sre

खादी के चोगे पहन डिग्रियाँ लीं नालन्दा विश्वविद्यालय के छात्रों ने

बिहार के राजगिर के पास स्थित नालन्दा विश्वविद्यालय में किसी समय पूरी दुनिया के छात्र अध्ययन के लिये आते थे। हजारों छात्र इसमें ज्ञान–विज्ञान के पाठ पढ़ते थे। शिक्षा से वैर रखने वाले अरब आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त कर दिया। बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षा केन्द्र का विध्वंस कर इसमें आग लगा दी। अब इस विश्वविद्यालय को नया जीवन दिया गया है। गत 27 अगस्त को विवि का पहला उपाधि–वितरण समारोह हुआ। राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने सफल छात्रों को डिग्रियाँ दी। विशेष बात यह थी कि श्री मुखर्जी सहित सभी छात्रों, अध्यापकों ने खादी के चोगे पहने।

खादी न केवल भारत के मौसम के लिये सबसे अच्छा पहनावा है बल्कि खादी के प्रयोग से अधिक हाथों को काम मिलता है। वर्तमान केन्द्र सरकार भी खादी का प्रयोग बढ़ाने के लिये संकल्प–बद्ध है। उक्त समावर्तन (डिग्री वितरण) समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज्य, बिहार के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, विवि के कुलपति व प्राध्यापक भी सम्मिलित हुए। सभी ने खादी के ही चोगे पहने हुए थे। मुम्बई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) ने भी अपने समावर्तन समारोह में खादी के ही प्रयोग की घोषणा की है।

बर 2016 7

[Fa]shion industry, consumers beginning to recognise khadi's value'

[INTER]VIEW: [RITU B]ERI | [FASHION DE]SIGNER

FASHION DESIGNER **Ritu Beri** *is behind the latest Vichar Vastra collection offered at Khadi outlets. She tells* **Ivinder Gill** *about the collection, how khadi has immense versatility for a designer and how it should be seen as a luxurious fabric made in India. Edited excerpts:*

What brief were you given to design the Vichar Vastra line for the Khadi and Village Industries Commission?
When I heard the Prime Minister quote Mahatma Gandhi—"Khadi is not just a fabric (*vastra*), but a serious thought (*vichar*)"—I decided to create something that can be worn by each and every Indian, and named the garment "Vichar Vastra". It's a simple, easy-to-wear shirt that has the versatility to be worn by one and all. It can be easily paired with pants, a *salwar*, a skirt or even with jeans. Priced at ₹1,299, it is affordable and a statement piece to promote khadi as not just a fabric, but a symbol of the Indian state of mind.

What other products are you designing under the same line?
We have many initiatives in mind, including fashion shows for kids, showcasing khadi. We will be doing impressive promotions and exhibitions related to khadi, both in India and abroad.

How else are you involved with the KVIC and khadi?
I love khadi and am doing my best to make khadi a global fabric, so that it's noticed by the youth. Banking on my experience of 25 years in the fashion industry, my effort will be to try and motivate people to wear khadi. My latest collection celebrates khadi and consists of Indo-western silhouettes, reflecting Indian charm with a modern flavour.

The silhouettes are a mix of our rich tradition with a contemporary look—the clothes are easy to wear, yet glamorous, essentially an eclectic blend of *ghagras*, *salwars*, *choga*-like jackets and easy-to-wear tops. Interesting details, a mix of appliqué, as well as unusual embroideries, constitute this versatile collection of khadi. The colour palette ranges from whites to pastels, metallics to blacks, enabling the freedom to create one's own chromatic world of fantasy.

Tell us about the campaign for Vichar Vastra and the celebrities roped in?
The campaign for Vichar Vastra is very simple; we reach out to people from all walks of life. Many celebrities and politicians have endorsed Vichar Vastra, including cricketer Virender Sehwag, politicians Meenakshi Lekhi, Shashi Tharoor, Pawan Verma, Jay Panda, journalist Rajat Sharma, NITI Aayog CEO Amitabh Kant, Medanta's Naresh Trehan, model Nayanika Chatterjee and singer Jasbir Jassi, to name a few. The collection will be available all over India soon.

Many celebrities and politicians have endorsed Beri's Vichar Vastra range, including railway minister Suresh Prabhu (left) and NITI Aayog CEO Amitabh Kant

Any comments on how the fashion industry is treating khadi?
Khadi is acknowledged as the most breathable and comfortable fabric ever. Today, the fashion industry and consumers are beginning to recognise its value and strength. They have started respecting it as one of the luxurious fabrics produced in India.

Khadi has vast scope and we need to explore its possibilities. I personally love khadi; my first few collections in 1990 were primarily in khadi. It's a very comfortable fabric great for India's climatic conditions.

The future for khadi is great. The endeavour is to encourage national and international fashion designers to create their collections using khadi. We need to be proud of this fabric and create an exclusivity that is so well deserved.